GOVERNMENT OF HARYANA
हरियाणा सरकार

बजट 2025-26

नायब सिंह

मुख्यमन्त्री, हरियाणा

वित्त मन्त्री के रूप में

बजट भाषण, 17 मार्च, 2025

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आज इस गरिमाशाली सदन के समक्ष हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2025–26 का राज्य बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर, सर्वप्रथम, मैं अपना शीश झुकाकर हरियाणा की श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी व्यापारियों, योग्य युवाओं, सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों और बहनों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ।

2. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र पर चलते हुए आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने वर्ष 2020 से हरियाणा में बजट पूर्व परामर्श की एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की थी।

3. इसका निर्वहन करते हुए मैंने इस वर्ष 02 जनवरी को गुरुग्राम, 09 जनवरी को हिसार, 13 जनवरी को कुरुक्षेत्र, 20 जनवरी को पंचकूला, 30 जनवरी को पानीपत एवं फरीदाबाद, 7 व 14 फरवरी को चण्डीगढ़, 3 एवं 4 मार्च को पंचकूला तथा 5 मार्च को चण्डीगढ में हरियाणा की अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ कुल 11 बैठकें की। इनमें मुझे आज के बजट प्रस्तावों के लिए 1592 सुझाव प्राप्त हुए।

4. इस परिपाटी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने 10 दिसम्बर, 2024 से एक ऑनलाईन पोर्टल भी शुरू किया। इसके माध्यम से हरियाणा के कोने–कोने से घर बैठे–बैठे लोगों ने मुझे बजट के लिए 8963 सुझाव भेजे। कुछ सुझाव मुझे ई–मेल और पत्रों के माध्यम से भी मिले। प्रदेश के मेरे दौरों के दौरान भी कई बार कुछ आमजन ने अपने लिखित सुझाव मुझे प्रस्तुत किए।

5. यकीन मानिए, मेरी निगाह में प्रदेश के कोने—कोने से मिले सुझावों को एकत्रित करने की यह प्रकिया महाकुंभ की तरह रही है। मैं हर उस आम और खास का आभारी हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव देकर मेरा पहला बजट बनाने में मुझे सहयोग दिया है।

6. कुल मिलाकर लगभग 11,000 सुझावों पर मैंने गहरा मनन और चिंतन किया। इन क्षणों में मैं दो तथ्यों को कभी नहीं भूला। पहला, गत विधानसभा चुनावों के लिए हमारे संकल्प पत्र को मिला भारी जनादेश और दूसरा, विश्व में तेजी से बदलता भू—राजनैतिक परिवेश और इससे उभर रही अनिश्चितताएं और नई आर्थिक चुनौतियां।

7. यह सर्व विदित है कि हम अपने संकल्प पत्र के 217 में से 19 वादों को पूरा कर चुके हैं और 14 वादों पर कार्य तेजी से प्रगति पर है। गत 18 नवम्बर में इस सदन द्वारा पारित अनुपूरक बजट से हमें ऐसा करने में काफी मदद मिली। इसके लिए मैं इस सदन का आभारी हूँ। मेरा मानना है कि आज के बजट प्रावधानों को इस सदन की स्वीकृति मिलने से हम लगभग 90 और संकल्पों को आगामी वित्त वर्ष में पूरा कर पाएंगे।

8. अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मैने अनेक ऐसे प्रस्ताव भी रखे हैं जिनसे हमारा प्रदेश उभरती हुई वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करने में सक्षम बनेगा। इस सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह संतुष्टि जताई थी कि 'अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए तिगुणी गति से काम कर रही है'। मैं समझता हूँ ऐसे प्रावधानों से यह सुनिश्चित होगा कि आगामी वर्षों में यह गति और भी तेज हो। इससे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में हरियाणा प्रदेश अपनी जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिस्से से कहीं बड़ा योगदान देने में सफल होगा।

9. इस उद्देश्य से किए गए मेरे छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस प्रकार हैः–

(i) भविष्य हमेशा ही अनिश्चितताओं और संभावनाओं से भरा होता है। परंतु आज की वैश्विक परिस्थितियों में आगे आने वाली चुनौतियों की चिंता करने, उनका पूर्व अनुमान लगाने और उनसे निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। हमारे विभिन्न विभाग अभी जिस विधि से अगले वर्ष के बजट प्रस्ताव बनाते हैं, उसे अब बदलना होगा। जलवायु परिवर्तन के जोखिम तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नई–नई तकनीकें कई क्षेत्रों, नौकरियों, उद्यमों और व्यापारों को प्रभावित करेंगी तथा इन आयामों में कुछ नई संभावनाएं भी पैदा करेंगी।

इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हरियाणा को **'भविष्य सक्षम'** बनाने के लिए **''डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर''** नाम से एक नया विभाग बनाया जाए। यह विभाग आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांप कर दूसरे सभी विभागों को नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा।

(ii) पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई–गवर्नेंस पर काफी बल दिया है। इसके चलते आज अनेक विभागों के पास नागरिक सेवाओं से सम्बंधित विशाल मात्रा में डेटा उपलब्ध है। मेरा मानना है कि डेटा–आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस ऑटोमेशन से जनसेवा की हमारी क्षमता एवं दक्षता और भी अच्छी हो सकती है। इस उद्देश्य को लेकर ''Haryana AI Mission'' की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। हर्ष की बात है कि विश्व बैंक ने इसके लिए 474 करोड़ रुपये का सहयोग करने का आरंभिक आश्वासन हमें दिया है।

(iii) इस AI मिशन द्वारा गुड़गांव और पंचकूला में एक–एक हब स्थापित किया जाएगा। हम इन द्वारा हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर पाएंगे जिससे वे नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे।

(iv) 4 जनवरी को हरियाणा निवास में मैनें हरियाणा के लगभग 60 ऐसे ऊर्जावान युवाओं से विचार विमर्श किया जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में अपने स्टार्टअप्स बनाए हैं। उन्होंने स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इंटर्नशिप शुरू करने, उनकी मेंटरशिप करने तथा उनके लिए सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कई सुझाव दिए। प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांडिंग और विक्रय से जुड़े उनके सभी सुझावों को स्वीकार करते हुए मैंने हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड को इन पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपये का एक **फंड आफ फंड्स** बनाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगी, जो हरियाणा के स्टार्टअप्स में निवेश करके हमारे प्रदेश को नवाचार और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

(v) प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए अनिवार्य है कि हम हमारे युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को नशे के जाल में फसने से बचा पाएं। इसके लिए मेरा ''संकल्प'' (SANKALP-Substance Abuse & Narcotics Knowledge, Awareness & Liberation Program Authority) नाम से एक नया प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण समूचे प्रदेश में नशे की मांग और आपूर्ति, दोनों को जड़ से खत्म करने के लिए सभी दूसरे विभागों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सारे समाज को साथ लेकर, हरियाणा के युवाओं को एक

विवेकपूर्ण विकास के मार्ग पर ले जाने का सतत प्रयास करेगा। इस प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक आवंटन करने का मेरा प्रस्ताव है।

(vi) इसी उपलक्ष्य में हम 'डंकी रूट' की गंभीर समस्या के निवारण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस उद्देश्य से इसी सत्र में हम एक बिल भी लेकर आएंगे। मुझे आशा है कि यह महान सदन उसे सर्वसम्मति से पारित करेगा। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत कार्यरत **हरियाणा ओवरसीज एम्पलोएमैंट सैल** और **हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम** के माध्यम से हम अपने इच्छुक युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाने के लिए सुरक्षित मार्ग भी प्रशस्त करेंगे।

(vii) हमने इसी वर्ष **मिशन हरियाणा–2047** नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरूआत भी की है। इसने हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंचाने और हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए एक प्रभावी योजना विकसित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। हर्ष की बात है कि मिशन ने वित्त वर्ष 2025–26 में ही कुछ जिलों के लिए अपनी योजनाओं का Proof of Concept बना कर देने का आश्वासन दिया है। इस मिशन के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपये के आवंटन का मेरा प्रस्ताव है।

10. अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पहले अर्थव्यवस्था और राजकोष की दशा और दिशा के बारे में सदन को अवगत कराने की पुरानी परंपरा है । इसी के निर्वहन में, मैं महान कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त जी के इन शब्दों से शुरूआत करना चाहता हूँः–

''हम क्या थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी''।।

11. वर्ष 2014–2015 में हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् जीडीपी 4,37,145 करोड़ रुपये थी जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2024–25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,951 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2024–25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपये है।

12. इस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारी कड़ी मेहनत से राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% की दर से बढ़ी है और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी है। इसके लिए मैं इस सदन को बधाई देता हूँ और 13वीं और 14वीं विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा दिए गए रचनात्मक सहयोग के लिए उनका भी आभार प्रकट करता हूँ।

13. वर्ष 2014–15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन जीडीपी का 1.90% था। वर्ष 2024–25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान है। इसी प्रकार यदि राजस्व घाटे को कुल बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2014–15 के 13.4% से कम होकर 2024–25 में 9.9% रहने का अनुमान है। स्पष्टतः दोनों दृष्टिकोणों से हमारे राजस्व घाटे में पिछले 10 वर्षों में काफी कमी आई है।

14. वर्ष 2014–15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) तत्कालीन जीडीपी का 2.88% था। वर्ष 2024–25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68% रहने का अनुमान है। याद रहे कि **राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम** अर्थात् **एफ आर बी एम एक्ट** के अनुसार किसी भी वर्ष किसी भी राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की उस वर्ष की जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः इसमें 2014–15 के 2.88% के मुकाबले अब 2.68% तक की गिरावट हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है।

15. वर्ष 2025–26 के लिए मेरे प्रस्तावों में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य है।

16. अर्थशास्त्र का सर्व मान्य सिद्धांत है कि सरकार को अपने राजस्व खर्चों के लिए ऋण नहीं लेना चाहिए। साथ ही, पूंजीगत खर्चे (Capital Expenditure) के लिए एक सीमा तक ऋण लेने में कोई बुराई नहीं होती, वरन इसे लेना भी चाहिए।

17. इसी लिए प्रभावी राजस्व घाटा राजकोषीय प्रबंधन का एक बेहतर संकेतक है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2014–15 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.89% था, जो वर्ष 2024–25 में कम होकर केवल 1.01% रहने का अनुमान है। इस कमी से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर बहुत बल दिया है।

18. अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद कई बार सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़े को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता हैं। सरकारी ऋण से संबंधित एफआरबीएम एक्ट के प्रावधानों के बारे में हमारे आलोचक जान बूझकर चुप रहते हैं। इसलिए, आपकी अनुमति से मैं हरियाणा सरकार के ऋण की स्थिति को एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ।

19. किसी भी वर्ष किसी भी राज्य का बकाया ऋण उस राज्य की जीडीपी के प्रतिशत की एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2014–15 में हरियाणा सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता उस समय के वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 6.67% बिंदु कम थी।

20. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024–25 में भी सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 6.67% बिंदु ही कम रहेगी। स्पष्टतः आज के बकाया ऋण की

प्रतिशतता निर्धारित सीमा से उतने ही प्रतिशत कम है जितनी यह वर्ष 2014–15 में था।

21. इतना ही नहीं, सरकार के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण, जिन्हें सरकार के ऋण के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता, में इन 10 वर्षों में एक भी रुपये की बढ़ौतरी नहीं हुई है। परन्तु इन दोनों तथ्यो को हमारे आलोचक छुपा लेते हैं।

22. हरियाणा सरकार के कुल 43 उपक्रम है। इनमे से 24 उपक्रम कम्पनी एक्ट में व 19 उपक्रम कॉपरेटिव सोसाईटीज एक्ट में पंजीकृत हैं। इन 43 उपक्रमों का वर्ष 2014–15 में कुल बकाया ऋण 69,922 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2023–24 में घट कर 68,295 करोड़ रुपये रह गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2008–09 में इन सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपये था।

23. अतः आकँड़े गवाह हैं कि जहाँ एक ओर 2008–09 से लेकर 2014–15 के बीच के 6 वर्षों में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपये से बढ़कर 69,922 करोड़ रुपये हो गया था, वहीं 2014–15 से लेकर 2023–24 के बीच की 9 वर्षों की अवधि में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण बढ़ने की बजाए 1627 करोड़ रुपये कम हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर जबरदस्त नकेल कसी है।

24. अध्यक्ष महोदय, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है।

25. यह चमत्कार संभव हो पाया आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़संकल्प से जिन्होंने उदय (UDAY) स्कीम को लागू किया, जिसके अंतर्गत बिजली निगमों के 25,950 करोड़ रुपये के ऋण वर्ष 2015–16 व 2016–17 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने खाते में ले लिए गए। श्री मनोहर लाल जी की इच्छा शक्ति से एचएसआईआईडीसी और एचएसवीपी की कार्य प्रणाली में

आमूल–चूल परिवर्तन किए गए। वर्ष 2023–24 के वास्तविक अनुमानों के हिसाब से हमारे 43 उपक्रमों में से 28 उपक्रम लाभ में है जिन्होंने 1746 करोड़ रुपये का शुद्व लाभ कमाया है। वर्ष 2014–15 में केवल 20 ही उपक्रम लाभ में थे, जिनका लाभ मात्र 450 करोड़ रुपये था।

26. इस सच्चाई के चलते मेरा सभी से अनुरोध है कि जब भी कोई नेता जनता को हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बारे में बताए तो यह जरूर स्पष्ट करे कि जब वे सत्ता में थे तो सरकार का ऋण जीडीपी का कितने प्रतिशत था और सरकारी उपक्रमों का ऋण कितना था।

27. अध्यक्ष महोदय, जहां राजकोष के कुशल वित्तीय प्रबंधन में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक सराहनीय भूमिका होती है वहीं वे अक्सर अपनी किसी भी स्कीम को बंद नहीं होने देना चाहते। इसलिए मैंने सभी विभागों को विशेष आग्रह किया कि वे अपनी उन स्कीमों को बंद करे जो अनुपयोगी हो गई हैं और जहां एक ही उद्‌देश्य वाली दो या अधिक स्कीमें चल रही है उनका वे विलय करें। मुझे खुशी है कि इस बजट में हमने 11 विभागों की 48 योजनाओं का विलय कर दिया है व 20 योजनाओं को समाप्त कर दिया है।

28. अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष के स्वास्थ्य पर इस दृष्टिपात के बाद अब वर्ष 2025–26 के हरियाणा बजट प्रस्तुतीकरण के ठीक पहले मैं हृदय की गहराइयों से इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

29. आप सभी ने 3 और 4 मार्च को रेड बिशप, पंचकूला में मुझे इस बजट के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए। आपको याद होगा कि मैंने पूरी तल्लीनता से आपके सभी सुझाव सुने थे और उन्हें नोट भी किया था। कुछ सदस्यों द्वारा मुझे लिखित सुझाव भी दिए गए थे।

30. मैं आशा करता हूँ कि आप भी आज पूरी तल्लीनता से मेरे हर प्रस्ताव को सुनेंगे। बीच–बीच में जब–जब आपको किसी प्रस्ताव में अपना सुझाव स्वीकृत हुआ दिखे तो आप उसका स्वागत करें; मुझे अच्छा लगेगा। मेरा विश्वास है कि हर सदस्य को बजट भाषण के अंत तक ऐसे कई अवसर मिलेंगे।

31. इस बजट को बनाने में हम सब ने मिलकर प्रयास किया है। मेरा मानना है कि इसीलिए यह बजट तेजस्वी बन पाया है। आप जानते हैं कि मिलकर प्रयास करने को संस्कृत में ''सह वीर्यं करवा वहै'' कहते हैं और प्रभु ऐसा करने पर परिश्रम के विषय या ''अवधीत'' को तेजस्वी करते हैं।

32. इसलिए, आइए बजट प्रस्तावों की शुरुआत से पहले शांति मंत्र का पाठ करते हैं :

ऊँ सहनाववतु

सहनौ भुनक्तु

सह वीर्यं करवावहै।

तेजस्विनावधीतमस्तु

मा विद्विषावहै।''

ऊँ शांति, शांति, शांति

33. अध्यक्ष महोदय अब मैं 2025–26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव रखता हूँ, जो वर्ष 2024–25 के संशोधित आंकडें 1,80,313.57 करोड़ रुपये से 13.7% अधिक है।

कृषि व सम्बन्धित प्राथमिक क्षेत्र

34. अध्यक्ष महोदय, कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियॉ हमारे छोटे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं और हमेशा रहेंगी।

35. हर किसान की लागत कम करना, उसकी फसलों की पैदावार को हर वर्ष बढ़ाते रहना, हर फसल को एमएसपी पर खरीद की गारन्टी देना, उसके खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखना, उसके पानी की हर बूंद से अधिक से अधिक उपज लेना, उसे अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और उसकी आय को लगातार बढाते रहना, हमारी सरकार की पिछले दस वर्षो की तरह इस वर्ष भी परम प्राथमिकताएं रहेगी।

36. 9 जनवरी को हिसार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े सैकड़ो किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाईयों और बहनों के साथ लगभग 5 घण्टे चले विचार–विमर्श में उन्होंने मुझे 161 सुझाव दिये।

37. मुझे खुशी है कि हर वक्ता ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ई–खरीद पोर्टल, मेरा पानी मेरी विरासत, भावान्तर भरपाई, फसल अवशेष प्रबन्धन प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती जैसी हमारी अनेक योजनाओं की भूरि–भूरि प्रशंसा की तथा इन सभी नवाचारों को आगे बढाने का आग्रह भी किया।

38. उस बैठक के प्रायः सभी सुझावों को इस बजट में मैंनें किसी न किसी रूप में शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। इनमें से छह नीतिगत सुझावों का मैं पहले वर्णन करना चाहूँगाः–

    (i) सभी किसानों का कहना था कि जहाँ एक ओर सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाने में पूरी मेहनत करती है, वहीं हमारे समाज की कुछ काली भेड़ें किसानों को नकली बीज व कीटनाशक बेच कर बर्बाद करने का प्रयास करती हैं। किसानों को इनके चंगुल से बचाने के लिए सदन के इसी सत्र में हम एक बिल लेकर आयेंगे। मेरा सभी मान्नीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस

प्रकार आपने पिछले सत्र में हरियाणा कृषि भूमि लीज बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था उसी प्रकार आप इस बिल को भी सर्वसम्मति से पारित करें।

(ii) मुझे बताया गया कि वर्तमान में जो कृषक उत्पादक संगठन अर्थात् एफपीओ एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत है, उन्हें तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है परंतु जो कृषक उत्पादक संगठन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है, वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए हम शीघ्र ही एक **नई बागवानी नीति** लाएंगे, जिसके तहत मूल्य संर्वधन, भण्डारण, प्रोद्यौगिकी, मार्केटिंग, प्राकृतिक व जैविक बागवानी को दोनों प्रकार के एफपीओ के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(iii) गत 8 मार्च को अंन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने यह घोषणा की है कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतू 1 लाख रुपये तक का ऋण लेती है, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उनके ब्याज का पूरा भार सरकार वहन करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मतस्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं को महिला उन्मुखी बनाया जायेगा एंव किसी भी योजनाओं में भी महिलाओं द्वारा लिए गए पहले 1 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

(iv) पोषक तत्वों से भरपूर गोबर–खाद फसलों के लिए अच्छा उर्वरक होती है। प्रदेश में गोबर खाद को व्यवस्थित तरीके से व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक नीति बनाई जाएगी।

(v) मोरनी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ किसानों को फसल उत्पादन में विशेष कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

यहां के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार शीघ्र ही एक विशेष कार्य योजना बनाएगी।

(vi) पशुपालकों की आय बढाने के लिए, बकरी और भेड़ की उच्च आनुवंशिक नस्लें, जैसे बीटल, सिरोही, मुंजल आदि, जो हरियाणा में नहीं पायी जाती है, उन्हें हमारे किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार आगामी वित्त वर्ष में एक नई योजना की शुरूआत करेगी।

39. मैनें कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2025–26 में जिन महत्वपूर्ण कदमों के लिए बजट प्रावधान किया है उनमें से मैं केवल 38 के बारे में आपको बताना चाहूँगाः–

(i) वर्ष 2024–25 के 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य के मुकाबले मैनें इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही, देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले ₹25,000/– के अनुदान को बढाकर ₹30,000/–किये जाने का मेरा प्रस्ताव है।

(ii) अभी तक कम से कम 2 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलता था। इस सीमा को घटा कर मैं एक एकड़ किये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(iii) मैंने लवणीय/नमकीन भूमि को पुर्नजीवित किये जाने के चालू वर्ष के 62,000 एकड़ के लक्ष्य को वर्ष 2025–26 में बढ़ाकर 1,00,000 एकड़ किये जाने का प्रस्ताव किया है।

(iv) "मेरा पानी मेरी विरासत योजना" के तहत मैं धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि ₹7000/–प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹8,000/–प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखता हूँ। साथ ही, जो ग्राम पंचायतें अपनी काश्त लायक भूमि को धान उगाने के लिए पट्टे

पर देने की बजाय खाली छोड़ेंगी, उन्हें भी अब यह प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

(v) सभी जानते हैं कि धान की सीधी बुआई में 20% से 30% तक कम पानी लगता है। धान की ऐसी बुआई अर्थात् डीएसआर की अनुदान राशि अभी ₹4000/— प्रति एकड़ है। मैं इसे बढ़ाकर ₹4500/— प्रति एकड़ का प्रस्ताव रखता हूँ।

(vi) धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अभी ₹1000/— प्रति एकड़ अनुदान राशि मिलती है। इसे बढ़ाकर, मैं ₹1200/— प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(vii) प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता के बावजूद कभी—कभी स्थानीय स्तर पर इनकी कमी देखने को मिल जाती है। किसानों के सुझाव के अनुरूप उर्वरकों के तर्कसंगत प्रयोग के लिए मैं इनकी बिक्री को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़े जाने का प्रस्ताव रखता हूँ। इससे नैनो यूरिया तथा नैनो डीएपी को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी।

(viii) फसलों को एक गेट पास जारी करने की पिछले खरीफ में शुरू की गई प्रथा को अब सभी फसलों पर लागू किया जायेगा।

(ix) ई—नाम के साथ संपूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडियों का नवीनीकरण किया जायेगा।

(x) गन्ने के घटते क्षेत्र और मैनुअल कटाई के लिए श्रमिकों की उपलब्धता की कमी से निपटने के लिए गन्ने की मशीन से कटाई कराये जाने के लिए हारवैस्टर पर सब्सिडी दिये जाने का मैं प्रस्ताव करता हूँ।

(xi) अभी प्रदेश में केवल 4 बीज परीक्षण लैब हैं जो करनाल, पंचकूला, सिरसा व रोहतक में स्थित हैं। अगले वित्त वर्ष में हरियाणा बीज प्रमाणीकरण ऐजन्सी द्वारा शेष 18 जिलों में भी एक–एक ऐसी बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएंगी।

(xii) प्रदेश में आज बागवानी के 11 उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं और 3 अन्य केंद्र निर्माणाधीन है। वित्त वर्ष 2025–26 में अम्बाला, यमुनानगर व हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्राबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

(xiii) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसम्बर, 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है कि इसके मुख्य परिसर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। यह विश्वविद्यालय, उपरोक्त सभी 14 उत्कृष्टता केंद्रों को बागवानी विज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करेगा।

(xiv) बागवानी में क्षेत्रीय विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चांदसोली, अंबाला में बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मेरे द्वारा इसी वर्ष 20 जनवरी को किया गया। वर्ष 2025–26 में दक्षिण हरियाणा के पलवल जिले में एक ऐसा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा।

(xv) अभी बागवानी मिशन प्रदेश के 19 जिलों में चल रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 में मेरा बाकी बचे हुए 3 जिलों नामतः फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी इसे लागू करने का प्रस्ताव है।

(xvi) इसके अतिरिक्त, सभी 22 जिलों में 400 बागवानी कलस्टरस के माध्यम से तथा जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2738 करोड़ रुपये की लागत से एक नया सत्त (Sustainable) बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025–26 में मैंने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 138 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

(xvii) मैनें तीन उभरती हुई गतिविधियों नामतः मशरूम कम्पोस्ट और स्पॉन, हाईटेक हाईड्रोपोनिक्स और ऐरोपोनिक्स तथा एफपीओ द्वारा बनाए गए 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरों को 7 रुपये 50 पैसे के बजाए 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का निर्णय किया है। इस आशय से हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को आदेश देकर एक नई कैटागिरी बनवाई जाएंगी।

(xviii) मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में अभी कुछ फसलों के लिए ही इन्टरकरोर्पिंग की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा अगले वित्त वर्ष से सारी फसलों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी।

(xix) हरियाणा सरकार द्वारा 2600 करोड़ रुपये की लागत से गन्नौर में बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी का निर्माण कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। इसके पहले चरण में 400 दुकानों के लिए 5 शेड्स तथा उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं आगामी नवंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। यह आधुनिक मंडी किसानों को सस्ती दरों पर बेहतर मूल्य, उन्नत भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किसानों का सीधा जुड़ाव होने से कृषि उत्पादों का निर्यात भी बढ़ेगा।

(xx) मैं गुरूग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए एक अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूलमण्डी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(xxi) गांव मनेठी जिला रेवाड़ी में मार्केट कमेटी द्वारा एक उप यॉर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(xxii) प्रदेश में हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो के लिए एक गोदाम बनाया जाएगा, जिसके लिए इसे 5 एकड़ भूमि तथा विमानों की पार्किंग, मरम्मत व रखरखाव के लिए 4 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।

(xxiii) हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम व यमुनानगर में आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन की क्षमता का एक सायलो भी बनाया जाएगा। हैफेड भारत सरकार की पीईजी योजना के तहत 30 लाख मीट्रिक टन की नई भण्डारण क्षमता उपलब्ध करवाएगा।

(xxiv) दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल और जिला कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल की मिल की स्थापना सार्वजनिक–निजी–भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत सुनिश्चित की जाएगी।

(xxv) देसी सांड के वीर्य की लिंग आधारित छंटाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से हिसार में शुक्राणु छंटाई (Sex Sorted Semen) प्रयोगशाला बनाये जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूँ।

(xxvi) मैं गौ–सेवा आयोग के तहत 1000 तक पशुओं वाली गौशालाओं को एक ई–रिक्शा तथा 1000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाओं को दो ई–रिक्शा उपलब्ध करवाये जाने

और गौशालाओं की क्षमता बढाने के लिए पंजीकृत गौशालाओं में 51 शैड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में दिये जाने के प्रस्ताव रखता हूँ।

(xxvii) लोगों की आस्था व गौ प्रेम को बनाए रखने के लिए हर जिलें में एक नया गौ अभयारण्य बनाने का भी मेरा प्रस्ताव है ताकि बेसहारा गौवंश को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया जा सके।

(xxviii) पशुपालक किसानों को पशुधन बीमा योजना के तहत एक किसान को अभी अधिकतम 5 पशुओं के बीमे की सीमा है। मैं इसे बढाकर 10 पशुओं तक किए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(xxix) मैंने 60 करोड़ रुपये की लागत से सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाईयों व उन्नत डायगनोस्टिक उपकरणों जैसे एक्स–रे, अल्ट्रासाउंड लगाने के लिए मैंने प्रस्ताव किया है। ये सेवाएं पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।

(xxx) सफेद झींगा के उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर लगाये जाने पर दिए जाने वाले अनुदान की 10 किलोवॉट की सीमा को बढ़ाकर 30 किलोवॉट करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

(xxxi) मैं सिरसा और भिवानी में सफेद झींगा व मछली के पालन को बढावा देने के लिए एक–एक एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(xxxii) प्रदेश के इतिहास में पहली बार **"मुख्यमन्त्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना"** के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 70 करोड़ रुपये की आवंटन प्रोत्साहन राशि सहकारी दूध उत्पादकों को दूध भुगतान के साथ ही दी जाएगी। वर्तमान

में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ प्रतिदिन औसतन 4.75 लाख लीटर दूध की खरीद करता है। वित्त वर्ष 2025–26 में इसे 15 प्रतिशत बढ़ाकर प्रतिदिन औसतन 5.45 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है।

(xxxiii) प्रदेश के हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र तथा प्रत्येक जिले में एक शीतलन केंद्र विकसित किया जाएगा।

(xxxiv) किसानों की पैक्सों की तरफ बकायाजात की समस्या के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(xxxv) गर्व की बात है कि 2021–22 में शुरू की गई हरित स्टोर नामक योजना के तहत 1250 स्टोर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खुल चुके है, जिनमें से 758 दुकानें मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही है। हरियाणा में हरित योजना के माध्यम से कुल लगभग 1 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है। मैं वर्ष 2025–26 में अतिरिक्त 750 हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(xxxvi) वर्तमान में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ 638 वीटा दूध के बूथ संचालित करता है। वर्ष 2025–26 में ऐसे 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे।

(xxxvii) हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा।

(xxxviii) सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए हरियाणा एग्रो इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन व हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ संयुक्त रूप से एक जूस प्रसंस्करण संयत्र स्थापित करेंगें।

40. अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग

की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 19.2% से बढ़ाकर 4229.29 करोड़ रूपये, बागवानी विभाग की आवंटित राशि को 95.50% से बढ़ाकर 1068.89 करोड़ रूपये, पशुपालन विभाग की आवंटित राशि को 50.9% से बढ़ाकर 2083.43 करोड़ रूपये, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 144.40% से बढ़ाकर 218.76 करोड़ रूपये, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 58.80% से बढ़ाकर 1254.97 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूँ।

सुशिक्षित हरियाणा

41. अध्यक्ष महोदय, इस बजट को बनाते समय क्षेत्रीय एवं विभागीय सोच से ऊपर उठकर आम हरियाणवी के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। ये विषय हैं : शिक्षा तथा स्वास्थ्य। यदि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो शिक्षा और स्वास्थ्य इसकी दो बाजूए हैं। मेरा मानना है कि विकसित हरियाणा के हमारे संकल्प की सिद्धि में सुशिक्षित तथा स्वस्थ समाज का सबसे बड़ा योगदान रहेगा।

42. हरियाणा में हर शिशु, हर किशोर, हर किशोरी, हर युवक और हर युवती को अत्याधुनिक एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा कैसे मिले, इसे लेकर 13 जनवरी को कुरूक्षेत्र में युवाओं के साथ, 20 जनवरी को पंचकूला में महिलाओं के साथ और 5 मार्च को चण्डीगढ़ में शिक्षाविदों के साथ की गई बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुझे अनेक सुझाव मिले।

43. हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विजन के अनुरूप बनाने तथा राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता देश में

सर्वश्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से इस बजट में किए गए केवल 27 नए प्रस्तावों का मैं यहां वर्णन करना चाहूँगा :—

(i) गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में आज 197 राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय कार्य कर रहे हैं। बहुत स्थानों से मुझे आम जन की मांग मिलती है कि उनके इलाको में भी ऐसे विद्यालय खोले जाए। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि वित वर्ष 2025—26 में राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। इससे डबवाली, नारनौल, नागंल चौधरी, सिवानी, हिसार, भट्टूकलां, गुहला, और पेहवा जैसे कई ब्लाकों के विद्यार्थियों को मॉडल संस्कृति स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा।

(ii) मैंने प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय को सैन्टर ऑफ एक्सीलैन्स इन स्पोर्टस के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे पुनर्गठन के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, राई, हरियाणा शिक्षा बोर्ड, भिवानी व शिक्षा विभाग द्वारा सामुहिक प्रयास किए जाएंगे।

(iii) इसी तरह मैंने प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय को सैन्टर ऑफ एक्सीलैन्स इन स्किलस के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव भी रखा है। ऐसे पुनर्गठन के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा शिक्षा बोर्ड, भिवानी व शिक्षा विभाग द्वारा सामुहिक प्रयास किए जाएंगे।

(iv) जिला अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में कुल 12 स्कूल दोहरी पाली में चल रहे हैं। वित वर्ष 2025—26 में इन विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार आधारभूत ढांचा तैयार कर इन्हें एकल पाली में

चलाए जाने का मेरा प्रस्ताव है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो वर्ष 2026–27 से बाकी जिलों के दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

(v) छोटी कक्षाओं से ही विद्यार्थियों की विज्ञान एवं प्रौद्यिगिकी विषयों में रूचि बढाने तथा इनमें उनके कौशल को विकसित करने के लिए प्रदेश के 13 जिलों में स्थित 50 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक–एक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2025–26 में 615 अन्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक–एक नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (STEM) लैब स्थापित की जाएगी। इस प्रकार एक भी जिला इनसे अछूता नहीं रहेगा। इनमें 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, 3–डी प्रिंटिंग व ए.आई जैसी आधुनिक तकनीकों की शिक्षा दी जाएगी।

(vi) यह चिंता का विषय है कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड दोनों में हरियाणा का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। राजकीय विद्यालयों में तो इन प्रतियोगिताओं के बारे में रूचि न के बराबर है। मेरा मानना है कि हमें इन दोनों प्रतियोगिताओं में हरियाणा के प्रतिभावान विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे खेल प्रतिस्पर्धाओं में हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत कर लाते हैं, कोई कारण नहीं है कि गणित ओलंपियाड में वे ऐसा न कर पाएं। अतः प्रदेश के विद्यार्थियों में गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष **''हरियाणा मैथ ओलंपियाड''** आयोजित करवाई जाएगी।

इसमें राजकीय और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों मे पढने वाले विद्यार्थी भाग ले सकेंगें।

इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 1,00,000 रूपये, 51,000 रुपये तथा 25,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान करने का मेरा प्रस्ताव है। चौथे से 100वां स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह राशि 10,000 रुपये होगी।

(vii) STEM को बढ़ावा देने के ही उद्देश्य से छठी से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को इसरो, डीआरडीओ तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र जैसे तकनीकी संस्थानों का भ्रमण करवाया जाएगा ताकि उन्हें उन्नत तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके।

(viii) आज की वैश्विक व्यवस्था में अधिक से अधिक भाषाओं के ज्ञान का बहुत महत्व है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप वित्त वर्ष 2025–26 में 9वीं तथा 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा को शामिल किया जाएगा।

(ix) राजकीय विद्यालयों में इच्छुक विद्यार्थियों को फ्रैंच भाषा पढ़ाने के लिए फ्रांस की सरकार ने हमारे अध्यापकों को गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण में सहयोग देने का वायदा किया है। शीघ्र ही हम उनके साथ इस आशय का MoU करेंगे।

(x) 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा द्वारा अपनी वेबसाइट पर गत 10 वर्षों के प्रश्नपत्र तथा मॉक टैस्ट भी उपलब्ध करवाये जाएंगे।

(xi) अपना स्टार्टअप बनाने की इच्छा विद्यार्थियों में प्रबल करने के उद्देश्य से शैक्षिणक सत्र 2025–26 से हर जिले में

उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित करने और चयनित टीमों को उनके विचार को व्यवसायिक मॉडल में परिवर्तित करने के लिए 1 लाख रुपये की राशि दिये जाने का भी मेरा प्रस्ताव है।

(xii) मैं विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की सुरक्षा के हित में हर पीएम श्री स्कूल, मॉडल संस्कृति स्कूल तथा हर क्लस्टर स्कूल कुल मिलाकर 1497 राजकीय विद्यालयों में सुरक्षा, निगरानी व अनुशासन के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(xiii) सभी 197 राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों एवं सभी 250 पीएम श्री विद्यालयों में ई–पुस्तकालयों का निर्माण करने तथा इन्हें स्कूल समय के उपरांत सामान्य जन के उपयोग के लिए भी खुला रखने का भी मेरा प्रस्ताव है।

(xiv) **बुनियाद** कार्यक्रम वर्ष 2022–23 में 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों की बुनियादी समझ को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था ताकि वे देश और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। 103 ऑनलाईन केन्द्रों के माध्यम से हर वर्ष करीब 6000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों की बढ़ती हुई रुचि और आग्रह पर 2025–26 शैक्षिणक सत्र से चार जिलों नामतः गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र व पानीपत में इसे ऑफलाईन माध्यम से भी शुरू किया जाएगा।

(xv) हरियाणा सरकार के हर विभाग के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों द्वारा हर महीने एक दिन किसी न किसी राजकीय विद्यालय में जाकर समय लगाना अनिवार्य किया जाएगा। वे इस दिन कम से कम दो–तीन घन्टे अपनी रूचि के विषय तथा अपने विभाग के प्रकल्पों पर विद्यार्थियों

से चर्चा करने के साथ–साथ उनकी करियर काउंसलिंग भी करेगें।

(xvi) हम हरियाणा को **उच्चतर शिक्षा** के लिए एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए मैंने वर्ष 2025–26 में राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों की तर्ज पर हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। इन आदर्श संस्कृति महाविद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षिक मानक, समर्पित शिक्षण सुविधाएं और विद्यार्थी–कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(xvii) उच्चतर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य में बस्ती है। इस ओर अभी तक तुलनात्मक कम ध्यान दिया गया है। अतः मैं हरियाणा के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन से **हरियाण राज्य अनुसंधान कोष** बनाये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(xviii) अभी महाविद्याालयों के STEM पाठ्यक्रमों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। इस हालात को बदलने के लिए मैं **"कल्पना चावला छात्रवृति योजना"** शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को एक लाख रुपये वार्षिक तक की छात्रवृतियाँ दी जाएंगी।

(xix) हरियाणा सरकार के सभी राजकीय महाविद्यालयों में पहले से ही सभी लड़कियों के लिए स्नातक स्तर तक ट्यूशन फीस माफ है। मेरे ध्यान में लाया गया हैं कि कुछ राजकीय विश्वविद्यालयों के प्रागंणों में स्थित महाविद्यालयों

में ऐसा नहीं है। ऐसे महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेस में पढ़ रही उन लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ करने का मैं प्रस्ताव रखता हूँ, जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है।

(xx) सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में **उद्योग – अकादमिक भागीदारी** को अनिवार्य किया जाएगा ताकि युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़े। कम से कम 10 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को ''सीखते हुए कमाएं'' मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा, जहां उद्योगों के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को ₹6,000/– का मासिक मानदेय मिलेगा। इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मैंने 36 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।

(xxi) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NSQF–अनुमोदित प्रमाणपत्रों और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों को प्रदेश में सभी रोजगार अवसरों के लिए मान्य किया जाएगा।

(xxii) व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे उनके अर्जित क्रेडिट को उच्च शिक्षा में भी मान्यता दिलवाई जाएगी।

(xxiii) विश्व कौशल ओलंपिक में हरियणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें, तो उन्हें सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यदि वे उद्यमिता में रूचि नहीं रखते तो उन्हें हरियाणा के स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में कौशल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार दिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। **मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता** नाम की इस नई पहल का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति प्रेरित करना और राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है।

(xxiv) **मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना** नामक एक अन्य नई योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2,000 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित उद्योगों और कम्पनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस दौरान उन्हें हर माह 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इस पहल से शैक्षणिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच का अंतर कम होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

(xxv) हरियाणा के सभी राजकीय शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आम जन के लिए भी खोला जाएगा। इससे वे अपनी ज्ञानवर्धन की इच्छा को पूरा कर सकेंगे और नवाचार व उद्यमशीलता के लिए संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। यह पहल राज्य में शिक्षा और नवाचार को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगी।

(xxvi) यह हर्ष की बात है कि हमारे सरकारी तकनीकी संस्थानों से पढने वाले बच्चों की मांग देश में व विदेश में बढ़ रही है। इसीलिए मैं राज्य सरकार के निलोखेडी, करनाल और पन्नीवाला मोटा, सिरसा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान (एचआईटी) में अपग्रेड किये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(xxvii) आज प्रदेश में कई बहुतकनीकी संस्थान हैं। इन सब में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के लिए एक

पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी जिसमें विभिन्न मापदन्डों जैसे की प्लेसमैन्ट, परीक्षा परिणाम, मशीनरी व उपकरणों की उपलब्धता, स्टॉफ की स्थिति, अनुशासन, खेल आदि के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान को 50 लाख, द्वितीय स्थान पाने वाले संस्थान को 25 लाख रुपये तथा तृतीय स्थान पाने वाले संस्थान को 10 लाख रुपये की धन राशि प्रदान की जायेगी।

44. अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान की तुलना में स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ाकर 17,848.70 करोड़ रूपये, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3874.09 करोड़ रूपये, आईटीआई विभाग की आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूँ।

स्वस्थ हरियाणा

45. अध्यक्ष महोदय, हर हरियाणवी जानता है कि पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था में न केवल भारी निवेश किया है। शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव से लेकर संचारी व गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं निवारण तक निरंतर मिशन मोड में काम किया है। यही कारण है कि 2013–14 के मुकाबले हमारा संस्थागत प्रसव 85.7% से बढ़कर 97.9% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 92% हो गई है। मातृ मृत्यु दर 127 से घटकर 110, नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19, शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 28 तथा 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 45 से घटकर 33 हो गई है। बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ की भावना पर सत्त् प्रयास से जन्म के समय लिंग अनुपात 868

से बढ़कर 910 हो गया है। इस वित्तीय वर्ष इन सभी मानकों में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेगें। आयुष्मान–चिरायु से लेकर मुफ्त डॉयलिसिस योजना तक हमारी अनेक अनूठी योजनाओं के सफल क्रियान्वन से आज हरियाणा का हर परिवार अच्छे अस्पतालों में ईलाज के लिए सम्भावित खर्च की चिन्ता से मुक्त है।

46. हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के हमारे संकल्प से डॉक्टर बनने के इच्छुक युवाओं के उत्साह में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आज पूरे प्रदेश में 15 मैडिकल कॉलेज, 10 दन्त चिकिस्ता कॉलेज, 19 फिजियोथैरेपी कॉलेज, 111 नर्सिंग कॉलेज तथा 182 नर्सिंग स्कूल कार्यरत है। पिछले 10 वर्षों में हमने एमबीबीएस की 1485 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 754 सीटें, डीएम एवं एमसीएच की 30 सीटें बढाई हैं। आज प्रदेश में एमबीबीएस की 2185 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 1043 सीटें तथा डीएम एवं एमसीएच की 37 सीटें हो गई है।

47. आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों पर पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने बहुत बल दिया है। मैं भारत सरकार का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया, जिसमें आज 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

48. मैं आज तक की उपलब्धियों का अधिक विवरण न करते हुए, व्यवस्था की जो कमियां अभी भी हैं, उन्हें दूर करने के लिए तथा **सर्वे संतु निरामयाः** की परिकल्पना को शीघ्रातिशीघ्र यथार्थ रूप देने के उद्देश्य से इस बजट में किए गए केवल 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव अब इस गरिमामयी सदन के समक्ष रखूंगाः–

(i) प्रदेश की माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्युदर, शिशु मृत्युदर तथा 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्युदर में और

उल्लेखनियां सुधार लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से मैं वर्ष 2025–26 में पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेन्द्रगढ़ के जिला अस्पतालों व मैडीकल कॉलेज नूंह में कुल 9 अति आधुनिक मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित का प्रस्ताव रखता हूँ।

(ii) वर्ष 2014–15 में हरियाणा में 200 बिस्तर वाले कुल 4 तथा 300 बिस्तर वाले 2 राजकीय अस्पताल थे। आज इनकी संख्या बढकर क्रमशः 18 व 3 हो गई है। पलवल, रोहतक एवं चरखी दादरी जिला अस्पतालों तथा अल आफिया जिला अस्पताल मांडी खेड़ा (नूंह) को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने की स्वीकृति दे दी गई है। वित्त वर्ष 2025–26 में हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरीय तथा झज्जर के जिला अस्पताल को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने का मैं प्रस्ताव करता हूँ।

(iii) मैंने अगले 2 वर्षो में हर जिला अस्पताल को उस शहर का उतने बिस्तर वाला सर्वोत्तम अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके वित्त वर्ष 2025–26 में मैं सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाओं तथा आधुनिकतम उपकरण जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउन्ड, ब्लड एनालाइजर और डिजीटल एक्सरे उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(iv) इसके अलावा, सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए निजी कमरों की व्यवस्था की जायेगी तथा उनके सहयोगियों के लिए भी आश्रय गृह की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(v) हर जिला अस्पताल में व हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बैड का एक क्रिटिकल केयर (Critical Care) ब्लॉक बनाने

और ब्लड बैंक की सुविधा का आधुनिकीकरण करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

(vi) दुर्घटनाओं के दौरान तथा ट्रामा में होने वाले ईलाज की सुविधाओं में बढ़ौतरी के लिए 14 जिलों नामतः गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, जीन्द, भिवानी, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर व चरखी दादरी के जिला अस्पतालों में 70 एडवांस लाईफ स्पोर्ट एम्बुलेंस एवं अन्य संरचनात्मक सुधारों के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2025–26 में 201.59 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं भारत सरकार का विशेष धन्यवाद करता हूँ।

(vii) अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कैंट में बनाया गए "अटल कैंसर केयर सेंटर" में लोग दूसरे राज्यों से भी कैंसर का इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पंचकुला, कुरूक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर व फरीदाबाद में कैंसर के मरीजों के लिए डे केयर सैन्टर भी चल रहे हैं। मैं शेष 17 जिलों में भी वित्त वर्ष 2025–26 में ऐसे डे केयर सैंटर बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(viii) पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भिवानी और महार्षि छायावान चिकित्सा महाविद्यालय, कोरियावास में शैक्षणिक सत्र 2025–26 के दाखिले के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अनुमति के लिए हम शीघ्र ही आवेदन कर रहे हैं।

(ix) वित्त वर्ष 2025–26 के लिए प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 2185 से बढ़ाकर 2485 सीटें करने का मेरा प्रस्ताव है।

(x) वित्त वर्ष 2025–26 में ही पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटैल तथा इसमें नवनिर्मित

750 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी शुरू कर दिया जाएगा।

(xi) प्रदेश में **निवारक स्वास्थ्य** के लिए शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नूंह में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

(xii) कुरुक्षेत्र में स्थित राज्य–स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए मैनें 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

(xiii) पंचकूला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई भूमि पर बने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा बीएएमएस की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं।

(xiv) गैर–ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन, व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जिला कुरुक्षेत्र के फतुहपुर गांव में लगभग 100 एकड़ भूमि पर श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2025–26 में आरम्भ कर दिया जायेगा। इसमें 63 सीटें बीएएमएस की तथा 82 सीटें स्नाकोत्तर स्तर की तथा डिप्लोमा इन फार्मेसी की 63 सीटों का प्रावधान रखा गया है।

(xv) रेवाड़ी व जीन्द में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किये जायेंगे।

(xvi) जिला अम्बाला के गांव चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज का प्रावधान किया जाएगा, इसके लिए गांव रामपुर–सरसेहड़ी सामुदायिक केंद्र में 25 बिस्तर का होम्योपैथिक अस्पताल शुरू कर दिया गया है।

(xvii) 421 आयुष औषधालयों एवं 111 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड किया गया है। इनमें से 201 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को एनएबीएच का

प्रमाणीकरण मिल गया है। वित्त वर्ष 2025–26 में शेष बचे 332 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को ऐसा प्रमाणीकरण लेने के लिए प्रर्याप्त बजट प्रावधान का प्रस्ताव मैंने किया है।

(xviii) स्वास्थ्य विभाग के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आम जन को आयुष चिकित्सा पद्धति तथा इस पर आधारित पोषण, आहार और दिनचर्या का मार्गदर्शन प्रदान करने की व्यवस्था वित्त 2025–26 में खड़ी कर दी जाएगी।

49. अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9391.87 करोड़ रुपये को 8.17% से बढ़ाकर वर्ष 2025–26 में 10,159.54 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

उद्योग व श्रम

50. अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक इकाईयों में निवेश का प्रदेश की अर्थव्यवस्था एंव रोजगार दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था को एक शरीर के रूप में देखा जाए तो उद्योग और श्रम इसकी दो टांगों के समान है। यदि ये बलशाली न हों तो अर्थव्यवस्था दौड़ नहीं पाएगी।

51. गुरूग्राम, यमुनानगर, पानीपत और फरीदाबाद जिलों के बीसियों औद्योगिक संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों पर मंथन उपरांत मैनें कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं। ये उद्यमियों एवं श्रमिकों, दोनों के हितों को बढ़ावा देंगें और राज्य में औद्योगिक विकास के एक नये युग का सूत्रपात करेंगे। बजट प्रस्तावों से पहले इनमें से केवल 3 महत्वपूर्ण निर्णय मैं आपसे साझां करना चाहूँगा जिन्हें 1 अप्रैल, 2025 से लागू कर दिया जाएगाः–

(i) हरियाणा में लगभग 2 लाख सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्योग (MSME) ऐसे क्षेत्रों में चल रहे हैं जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं है। विशेष रूप से यमुनानगर, गुरूग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, अम्बाला, करनाल और पंचकूला जिलों में इस कारण ये उद्योग हमारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। साथ ही, वर्षो से संचालित हो रही कई ऐसी फैक्ट्रीयों को इस कारण फैक्ट्री लाइसैन्स, फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुमतियां, श्रम विभाग की अनुमति, ट्रैड लाईसैन्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र, इत्यादि लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मान्नीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की लगभग 2145 अनाधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है। अब समय आ गया है कि हम अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों पर भी उसी प्रकार ध्यान दें। अतः हमने निर्णय लिया है कि कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाईयाँ कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं, यदि सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर अपना आवेदन करेंगी तो ऐसी सभी औद्योगिक इकाईयों को सरकार द्वारा समूह के आवेदन पर अंतिम निर्णय लिये जाने तक सभी विभागों द्वारा वैध औद्योगिक ईकाई माना जाएगा।

(ii) पूर्व में एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी में हस्तांतरित हुई औद्योगिक संपदाओं में लगे उद्योगों के मालिकों को ट्रांसफर, आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी), प्रोजेक्ट कम्पलीशन सर्टिफिकेट इत्यादि लेने में आ रही कठिनाईयों को समाप्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब एचएसआईआईडीसी उन प्लॉट धारकों को केवल एचएसवीपी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्रों की शर्तों व नीति के अनुसार

नियंत्रित करेगा न कि एचएसआईआईडीसी की अपनी ईएमपी के अनुसार।

(iii) अब से एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी, पंचायतों व अन्य सरकारी विभागों द्वारा इएसआईसी अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों के लिए भूमि का आवंटन रियायती दरो पर किया जाएगा।

52. अध्यक्ष महोदय, इन तीनों नीतिगत निर्णयों के अतिरिक्त एचएसआईडीसी भी 1 अप्रैल 2025 से अपनी अब तक की कार्यप्रणाली में निम्न नए परिवर्तन लाएगी। ये इस प्रकार हैंः–

(i) सभी औद्याोगिक सम्पदाओं में डॉरमिट्रीज और एकल कक्ष इकाईयों का निर्माण किया जाएगा। इससे श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधा उपलब्ध हो पाएगी।

(ii) सभी औद्योगिक संपदाओं में Incubation Centre बनाए जाएगें ताकि स्टार्टअपस को सस्ती दरों पर कार्य करने की सुविधा मिल सके।

(iii) आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संपदाओं में मल्टी–लेवल पार्किंग की सुविधा प्रदान की जायेगी। इससे पार्किंग की समस्या का समाधान होगा और उद्योगों को उचित व्यवस्था मिलेगी।

53. मैं माननीय सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2025–26 में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :–

(i) हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाईल पालिसी 2022–25 की अवधि दिसम्बर 2026 तक बढ़ाई जाएगी और इसके अंतर्गत पात्र परियोजनाओं की उपरी संख्या सीमा को समाप्त कर दिया जायेगा।

(ii) एचएसआईआईडीसी द्वारा आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 नये औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित करने के लिए ई–भूमि पोर्टल पर वर्ष 2025–26 की शुरूआत में ही

भूमि की मांग दर्ज कर दी जाएगी। साथ ही, किसानों को लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी के विकल्प भी दिए जाएंगे।

(iii) भारत सरकार के "एक जिला एक उत्पाद" (One District One Product) कार्यक्रम के अनुरूप, राज्य सरकार "पद्मा नीति" के तहत "एक ब्लॉक, एक उत्पाद" कार्यक्रम लागू कर रही है। स्थानीय संसाधनों एवं मौजूदा सूक्ष्म उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए जींद, अंबाला और करनाल जिलों में तीन नये औद्योगिक क्लस्टरों को अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष में, अलग–अलग जिलों में 10 नए औद्योगिक क्लस्टरों को फास्ट–ट्रैक मोड पर स्वीकृति दी जाएगी।

(iv) स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने लघु एवं मध्यम उद्योगों को CAQM मानकों के अनुपालन में सहायता प्रदान करने के लिए अब एक नई योजना के अन्तर्गत उद्योगों में लगे जेनरेटर्स को स्वच्छ, पर्यावरण–अनुकूल ईंधन में बदलने एवं रैट्रोफिट एमिशन कन्ट्रोल डिवाइस (RECD) उपकरणों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का मेरा प्रस्ताव है।

(v) हरियाणा को **"जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र"** के रूप में विकसित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। इस दिशा में एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए आई एम टी मानेसर को चुना गया है। यहां जल संरक्षण एवं हरित पहल के तहत 55 MLD के CETP से शोधित जल को रीसाइकिल कर पूरे औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास, सेंट्रलाइज्ड फायर सिस्टम तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा ताकि औद्योगिक कचरे और जल संसाधनों का सतत उपयोग हो सके।

(vi) खरखोदा में आईएमटी का विस्तार किया जाएगा, जिससे यहां औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जों के निर्माण के लिए ई–वी पार्क स्थापित किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में हरित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।

(vii) एसएसआईआईडीसी द्वारा अम्बाला शहर में पहले चरण में कम से कम 800 एकड़ भूमि में आईएमटी अम्बाला की स्थापना की जाएगी।

(viii) एचएसआईआईडीसी द्वारा राई औद्योगिक संपदा, आईएमटी बावल और आईएमटी मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप श्रमिकों के लिए 5–5 एकड़ भूमि डॉरमिट्रीज और एकल कक्ष के निर्माण के लिए उपलब्ध कराएगा। इन स्थलों पर ऐसी इकाईयों के निर्माण के लिए श्रम विभाग हरियाणा और हाऊसिंग फार ऑल विभाग द्वारा एचएसआईआईडीसी को सहयोग राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। निर्मित इकाईयां एचएसआईआईडीसी के औद्योगिक संपदाओं में कार्यरत श्रमिकों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक एंव वार्षिक किराए पर उपलब्ध कराई जाऐगी। इन आवासीय इकाइयों का दैनिक संचालन व प्रबन्धन स्थानीय औद्योगिक संगठनों द्वारा किया जायेगा । प्रत्येक सम्पदा में 500 एकल कक्ष इकाइयों और 50 डॉर्मिट्री इकाइयों का प्रावधान किया जाएगा।

(ix) हरियाणा सरकार, भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तर्ज पर "मेक इन हरियाणा" कार्यक्रम का प्रारूप बनायेगी, जिसके तहत राज्य को निर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु सरकार विभिन्न योजनाएँ लागू करेगी। इस दिशा में, सरकार द्वारा उद्योगपतियों को

आकर्षित करने के लिए वित्तीय एवं गैर–वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

(x) हमारी कई नीतियों जैसे औद्योगिक नीति 2020, टैक्सटाइल नीति 2022–25, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति 2019, आईटी आईटीएस नीति 2017, एचएसआईडीसी की इएमपी नीति 2015, हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति 2022, हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022, फार्मास्युटिकल नीति 2019, कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018, आईटी ईएसडीएम नीति 2017,एमएसएमई नीति 2019, आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा नीति 2024 व अन्य उद्योग एवं श्रम सम्बन्धित नीतियों को कालांतर में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बदलाव की भी आवश्यकता है । इनके नये प्रारूप वर्ष 2025–26 में तैयार कर लिए जायेंगे।

54. अध्यक्ष महोदय अब में श्रम विभाग के निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:–

(i) हरियाणा प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दरों को हर वर्ष महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाया जाता हैं। इस बढ़ोतरी के चलते अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें जो वर्ष 2015 में 7600/– रुपये निर्धारित की गई थी, वह अब बढ़कर 11001.76/– रुपये हो गई है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार न्यूनतम मजदूरी के मूल दरों का पुनरीक्षण एवं संशोधन करेगी।

(ii) हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए अभी 9 श्रम न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें जिला अम्बाला, पानीपत, हिसार और रोहतक में एक–एक, गुरूग्राम में दो व फरीदाबाद में तीन श्रम न्यायालय हैं। विवाद निपटान की

प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए इस वित्त वर्ष में श्रम न्यायालयों की संख्या को बढ़ाकर 14 किया जायेगा।

(iii) अध्यक्ष महोदय, बावल और बहादुरगढ़ में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल भवनों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष 2025–2026 में पूरा किया जाएगा। पंचकूला में ईएसआई डिस्पेंसरी भवन का निर्माण भी आगामी वित्तीय वर्ष 2025–2026 में पूरा किया जायेगा।

(iv) अस्पताल एवं डिस्पेंसरी बनाने हेतु एचएसआईआईडीसी द्वारा साहा, सोहना, खरखौदा, बहादुरगढ़, करनाल, फर्रुखनगर, चरखी दादरी, छछरौली, कोसली, घरौंडा, कैथल, कुरुक्षेत्र, पटौदी, गोहाना में ईएसआईसी नई दिल्ली को रियायती दरों पर भूमि दी जाएगी।

(v) गिग वर्कर्स को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैं एक नई योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इसके तहत राज्य में कार्यरत सभी गिग वर्कर्स के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जहाँ वे स्वयं को पंजीकृत कर सकेंगे। यह पोर्टल गिग वर्कर्स को विभिन्न सरकारी योजनाओं और अवसरों से जोड़ने का कार्य करेगा। पोर्टल पर पंजीकृत सभी गिग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना के अन्तर्गत गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य, दुर्घटना और जीवन बीमा जैसी आवश्यक सुरक्षा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य गिग अर्थव्यवस्था में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करना है, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकें और हरियाणा के आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनें।

(vi) 5 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना नक्शा व कारखाना लाइसेंस आवेदन पर निर्णय करने तथा 10 एकड़ तक के

उद्योगों के कारखाना लाइसेंस का नवीनीकरण करने की शक्तियाँ जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त को दी जाएगी।

55. एचएसआईआईडीसी ने मार्च, 2022 में आईएमटी खरखौदा में 800 एकड़ जमीन मारूति सुजुकि इंडिया लिमिटेड को अलॉट की थी। इस प्लांट का भूमि पूजन माननीय प्रधानमन्त्री जी ने विडियों कॉन्फैन्स के माध्यम से दिनांक 28.08.2022 को किया था। आज वहां मारूति ने अपनी व्यावसायिक उत्पादन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि हमारी सरकार औद्योगिक जगत को जो कहती है वो करके दिखाती है।

56. अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार उद्योग और श्रम को एक दूसरे का पूरक मानती है और इनके बेहतर समन्वय व सहयोग को प्राथमिकता देते हुए मैं एक **उद्योग–श्रमिक–मैत्री परिषद** का गठन करने की घोषणा करता हूँ। इस परिषद की अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा। यह परिषद मेरे द्वारा शुरूआत में बताए गये 6 नीतिगत निर्णयों की नियमित अंतराल पर समीक्षा करेगा जिससे औद्योगिक विकास को और अधिक गति मिलेगी।

57. अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन सुझावों पर हमने निर्णय नहीं लिए हैं, उन पर भी हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संभावित उपायों को तलाशेंगे व उपरोक्त सभी निर्णयों को न केवल सिद्वांत रूप से बल्कि व्यावहारिक रूप से भी क्रियान्वित करने के लिए कार्य करेंगे।

58. अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान की तुलना में उद्योग और वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को 805.75 करोड़ रुपये से 129.37% बढ़ाकर 1848.12 करोड़ रुपये, श्रम विभाग की आवंटित राशि को 74.58 करोड़ रुपये से 29.80% बढ़ाकर 96.81 करोड़ रुपये, का प्रस्ताव रखता हूँ।

खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता

59. हरियाणा के खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन करते आ रहे हैं। इसमें खिलाड़ियों की मेहनत के साथ–साथ राज्य की खेल संस्कृति और सरकार की प्रभावी नीतियों का भी योगदान है। हरियाणा खेल अवसंरचना को और अधिक सशक्त बनाने, उभरते खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने और राज्य को एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि हेतू वित्त वर्ष 2025–26 के लिए कुछ नए प्रस्तावों कों मैं यहां बताना चाहूगांः–

    (i) राज्य के 5 विश्वविद्यालयों, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गुरू जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, रेवाड़ी में नए खेल उत्कृष्टता केन्द्र खोले जाऐंगें।

    (ii) वर्ष 2036 में होने वाले ओलम्पिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के कम से कम 36 मैडल लाने के लक्ष्य से ''MISSION OLYMPICS 2036 विजयीभव'' योजना का आरम्भ किया जाएगा जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

    (iii) खिलाड़ियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक कठिनाइ का सामना न करना पड़े और वे बिना किसी अनिश्चितता के भय से मुक्त होकर पूर्णतः अपना ध्यान अपने खेल पर केंद्रित कर सके, इस उद्देश्य से मैं वित्त वर्ष 2025–26 में खिलाड़ी बीमा योजना लाने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये तक का मैडिकल कवरेज दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार के द्वारा भरा जाएगा।

(iv) अखाड़ों को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उच्च गुणवता बनाए रखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपये का ईनाम दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपये का ईनाम दिया जाएगा।

(v) राज्य के खेल परिसरों के बेहतर परिचालन व रख–रखाव के लिए पायलट आधार पर दो खेल परिसरों को पीपीपी मोड पर चलाने के लिए दिया जाएगा। अगर इस प्रयोग के नतीजे अच्छे आते हैं तो कुछ अन्य परिसरों को भी इसी नीति से चलाने हेतू चिन्हित किया जाएगा।

(vi) राज्य में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस सरकार द्वारा हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना 2023–24 में शुरू की गई थी, जिसमें आठ खेलों वॉलीबॉल, फुटबाल, बास्केटबाल, हैण्डबाल, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो व क्रिकेट के उपकरण नगर निकायों और पंचायतों के माध्यम से आबंटित किए जाने का प्रावधान है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि खेलों के प्रति रूझान बढ़ाने के लिए हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना में भारत्तोलन और योग को भी शामिल किया जाएगा।

(vii) प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी।

(viii) 01 अप्रैल, 2025 से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृति को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह तथा 15 से 19 वर्ष के खेल नर्सरी खिलाडियों की छात्रवृति को बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा।

(ix) 01 अप्रैल 2025 से आवासी अकादमी के खिलाड़ियों की डाईट मनी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी।

(x) खिलाड़ियों की सुविधा के लिए ''खेलों हरियाणा ऐप'' लांच की जाएगी जिसके जरिए वे अपनी खेल प्रयोजन व प्रदर्शन सम्बन्धी तथा अन्य पहलूओं को डिजिटल तरीके से प्रबन्धित कर पांएगें। इसका सारा खर्च सरकार वहन करेगी और खिलाड़ियों को इसकी सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी।

(xi) राज्य के हर इलाके में खेल सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी खेल स्टेडियमों की जीआईएस मैपिंग करवाई जाएगी व ऐसे 10 गांवों/कस्बों जिनमें 10 किलोमीटर तक कोई सरकारी खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं है, वहां नये स्टेडियम उपलब्ध करवाने का कार्य शुरू किया जाएगा।

(xii) ओलम्पिक स्तर पर पदक विजेता कोई भी खिलाड़ी यदि अपने गृह जिले में खेल अकादमी खोलना चाहे तो उसे सस्ती दरों पर 5 करोड़ तक का लोन बैकों के माध्यम से दिलवाया जाएगा जिस पर सरकार द्वारा ब्याज पर दो प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी।

60. युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, क्योंकि वे न केवल वर्तमान का निर्माण करते हैं बल्कि भविष्य की नींव भी रखते हैं। हरियाणा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। "युवा सशक्तिकरण" केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक संकल्प है, जिसके तहत उन्हें बेहतर अवसर, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बन सकें। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025–26 के बजट के कुछ नए प्रस्ताव इस प्रकार हैं:–

(i) राज्य व जिला स्तर पर अत्याधुनिक अवसरंचना वाले कौशल केंद्र बनाये जायेगें जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त प्रमाणन कार्यक्रम की कौशल सम्बिधत प्रशिक्षण, छात्रावास और विदेशी भाषा सीखने की सुविधा दी जाएगी।

(ii) पीपीपी मोड पर सभी जिलों में उत्कृटता केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

(iii) युवाओं की कौशल क्षमताओं को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष जिला और राज्य स्तर पर ओपन कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

(iv) राजकीय आई0टी0आई0 संस्थानों में मशीनरी एंव उपकरणों को उन्नत करने के लिए गत वर्ष में 39 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में इस वर्ष बजट प्रावधान बढाकर 90 करोड़ रुपये किया गया है।

(v) राजकीय आईटीआई के एम्प्लॉएबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर स्कूली विद्यार्थियों को करियर काउन्सिलिंग प्रदान करने के लिए नजदीकी राजकीय विद्यालयों का सहयोग करेंगे।

61. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 1381.78 करोड़ रुपये को 41.97% से बढ़ाकर वर्ष 2025–26 में 1961.79 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

पंचायती राज व ग्रामीण विकास

62. राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्षो में इससे सम्बन्धित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है । पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतू वित्तीय संसाधनों को बढाने के साथ ही नवाचारों को भी अपनाया जायेगा। मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया था की एक हजार से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतो की कच्ची फिरनियों को पक्का करवाया जायेगा। हमने

अब तक ऐसी 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 69.11 करोड़ की लागत से पक्का करवाया है, और आगामी वर्ष में इन गांवों की बची हुई सभी कच्ची फिरनियों को पक्का करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

63. प्रत्येक गांव मे एक महिला चौपाल बनाने के संकल्प की पूर्ति हेतू हमने प्रथम चरण में 754 गावों को चिन्हित किया है । मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूँ कि प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्षो से अधूरे पड़े हुए लगभग 600 से अधिक भवनों को लगभग 64 करोड़ रुपये की राशि से पूर्ण करवाया जायेगा ताकि उन्हें उचित प्रयोग में लाया जा सके।

64. महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिन लाभार्थियों को 15 वर्ष पूर्व प्लाट तो आंवटित किये गये थे परन्तु किसी कारणवश कब्जा नही दिया जा सका था, ऐसे लगभग 7300 पात्र परिवारों को विशेष अभियान चलाकर कब्जा दिया जा चुका है, तथा शेष पात्र परिवारों को भी "मुख्यमन्त्री ग्रामीण आवास योजना" के माध्यम से 100 वर्ग गज तक के प्लाट आवंटित किये जायेंगें । "महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना" के अर्न्तगत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पेयजल उपलब्ध करवाई जायेगी । इस कार्य के लिए मैं विशेष तौर पर 200 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

65. हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 891 ई–लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम तैयार कर दिएहैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार शेष ग्रामीण क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा।

66. माननीय प्रधानमन्त्री जी ने "आजादी का अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर मिशन का शुभारम्भ किया था जिसके तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है । हमने मनरेगा, पोंड अथॉरिटी और प्रधानमन्त्री कृषि सिचांई

योजना से 1645 अमृत सरोवर के लक्ष्य के सापेक्ष 2088 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित किया है और आगामी वर्ष में हम पूरे राज्य में 2200 नए अमृत सरोवर बनायेंगे।

67. स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार कर सभी गांवों को "मॉडल गांव" बनाना है। राज्य सरकार महाग्रामों तथा 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को "हॉपर टिपर डंपर" भी प्रदान करेगी जिससे इन पंचायतों में कचरा प्रबन्धन व्यापक स्तर पर किया जा सके । साथ ही, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तर्ज पर घर–घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को यह कार्य देने की योजना बनाई है और इन्हें इस कार्य के लिए मैं गांव की जनसंख्या के अनुपात में मासिक मेहनताना दिये जाने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

68. अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में एक व्यापक सुधार की आवश्यकता को मैंने अनुभव किया है। मेरा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जब भी एचईडब्लयू पोर्टल पर कोई निविदा लगाई जाएगी तो सम्बंधित ग्राम पंचायत को सूचना दी जाएगी।

69. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 5629.18 करोड़ रुपये को 29.93% से बढ़ाकर वर्ष 2025–26 में 7313.98 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

शहरी स्थानीय निकाय

70. अध्यक्ष महोदय, शहरों की सरकारों अर्थात् नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए वित्त वर्ष 2025–26 में उन्हें कर एवं शुल्क के निर्धारण की स्वतंत्रता दी जाएगी। संपत्ति कर, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन

शुल्क, पानी व सीवर शुल्क जैसे करों और शुल्कों का निर्धारण वे हरियाणा सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के बीच कही भी कर सकेंगे।

71. शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नीति के अनुसार, सफाई कार्यों की निविदाओं में अनुसूचित जाति के सदस्यों व महिलाओं द्वारा गठित सहकारी समितिओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 50 प्रतिशत निविदाएं सफाई मित्रों और उनके समूहों को आवंटित करने की नीति आगामी वित्त वर्ष 2025–26 में अधिसूचित की जाएगी।

72. सभी शहरों में जल निकासी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये का शहरी जल निकासी कोष स्थापित करने का मैं प्रस्ताव करता हूँ। यह समर्पित कोष स्थायी बाढ़ प्रबंधन करने तथा शहरों और शहरीयों को भविष्य की आपदाओं से सुरक्षित रखने के प्रकल्प शुरू करेगा।

73. सभी बड़े शहरों के जो पुराने इलाके अव्यवस्थित तौर से बसे हुए हैं, उन्हें पुनः विकसित किया जायेगा। इस कार्यो में सड़कों के सभी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, विशेषतः सड़को को पैदल चलने योग्य बनाने हेतू राज्य सरकार मौजूदा सड़क ढांचे को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करेगी। प्रथम चरण में 1000 किलोमीटर के राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) का विकास किया जायेगा।

74. राज्य सरकार नगर पालिकाओं को मशीनरी और उपकरण प्रदान करके स्वच्छता, सड़क सफाई, सीवरेज सफाई, सड़क मरम्मत, बागवानी आदि के संबंध में तेजी से और कुशल तरीके से बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2025–26 में सभी नगर पालिकाओं और परिषदों को वैक्यूम सकर एंव क्लीनर, ट्री ट्रिमिंग मशीन, बागवानी श्रेडिंग मशीन, छोटी स्वीपिंग मशीन, पैचवर्क मशीन, रोड रोलर, वॉशिंग/स्प्रिंकलिंग मशीन जैसी मशीनरी और उपकरण प्रदान करने का मेरा प्रस्ताव है।

75. राज्य सरकार खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने और युवाओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से सभी नगर पालिकाओं में एक खेल परिसर का निर्माण करेगी। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक खेल सुविधाओं को सशक्त बनाना और फिटनेस एवं उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

76. रोहतक और गुरूग्राम में बनाए गए मल्टीलेवल पार्किंग की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में भी मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। यह पहल पार्किंग की समस्याओं का समाधान करेगी और शहरों में यातायात प्रबंधन को सुगम बनाएगी।

77. पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं यमुनानगर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

78. राज्य सरकार विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए अति–आधुनिक पार्क विकसित करेगी। इन पार्कों में व्हीलचेयर के अनुकूल बुनियादी ढांचा, इंटरैक्टिव सेंसरी जोन और समावेशी खेल क्षेत्र होंगे, ताकि सभी के लिए एक आनंददायक और सुलभ अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

79. पिछले 10 वर्षों में 75 पुराने कचरा स्थलों से 101 लाख मीट्रिक टन कचरे में से लगभग 69 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करके 109 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है। जिसका उपयोग हरित क्षेत्र पार्क और सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 में सभी पुराने कचरा स्थलों को 100 प्रतिशत साफ करने के लक्ष्य के लिए मैंने प्रावधान किया है।

80. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 4091.95 करोड़ रुपये को 38.5% से बढ़ाकर वर्ष 2025–26 में 5666.28 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

नगर एवं ग्राम नियोजन

81. वर्ष 2020 में लागू की गई "**समाधान से विकास**" स्कीम में अब तक 343 कॉलोनाइजरों ने 3430 करोड़ रुपये को बकायाजात जमा करवाए हैं। इस स्कीम की अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। सरकार ने इसे 30 सितम्बर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

82. वित्त वर्ष 2024–25 में विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा विभिन्न मैट्रो प्राधिकरणों को ईडीसी से 2749 करोड़ रुपये तथा आईडीसी में से 476 करोड़ रुपये की राशि इनके विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की है। मैं वित्त वर्ष 2025–26 में इडीसी से 3000 करोड़ रुपये तथा आईडीसी से 600 करोड़ रुपये, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरूग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों के विकास कार्य के लिए देने का प्रस्ताव रखता हूँ।

83. 5452.72 करोड़ रुपये की लागत से गुरूग्राम में बनाए जाने वाली मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लम्बी मैट्रोलाईन का निर्माण कार्य, राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम, गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL), द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार 4,556.53 करोड़ रुपये वहन करेगी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत सिविल निर्माण कार्य मई 2025 में प्रारंभ किया जाएगा। इस मैट्रो लाइन के शुरू होने से गुरुग्राम की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूती मिलेगी।

84. वित्तिय वर्ष 2025–26 के लिए जीएमडीए का कुल बजट लगभग 2933.56 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 917 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 42 प्रमुख परियोजनाएं और 1750 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी के

लिए 23 प्रमुख परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें मुख्य रूप से चंदू और बसई में 100 एमएलडी डब्ल्यूटीपी और धनवापुर, बेहरामपुर और सैक्टर 107 में 100 एमएलडी एसटीपी की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त एसपीआर और देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

85. फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) ने मास्टर वाटर सप्लाई और सीवरेज की अवधारणा को बढ़ाने के लिए 3400 करोड़ रुपये से वर्ष 2031 तक की अनुमानित आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक योजना को अनुमोदित किया है। इस कार्य की शुरूआत वित्त वर्ष 2025–26 में सुनिश्चित की जाएगी।

86. ग्रामीणों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने तथा उन्हें शहरों के बराबर लाने के लिए शहर जैसी सुविधाएं बनाने के लिए मैंने नगर एवं ग्राम नियोजना विभाग को गांवों में भी नियोजित विकास की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2025–26 में पहले चरण में 21 महाग्रामों को पायलट परियोजना के रूप में ''महाग्राम–महायोजना'' की तैयारी की जाएगी, जिसमें गांव की आबादी, फिरनी तथा आस–पास के क्षेत्र को चिन्हित कर डवेल्पमेंट प्लान बनाया जाएगा।

87. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पिछले 3 वर्षों की अवधि में विभिन्न शहरी सुधार कार्य किए हैं, जिसके लिए विभाग को भारत सरकार से 616 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ।

88. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 140.23 करोड़ रुपये को 65.0% से बढ़ाकर वर्ष 2025–26 में 231.41 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

सबके लिए आवास

89. अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की सोच है कि राष्ट्र के हर नागरिक का यह अधिकार है कि उसके पास अपना एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर हो। राज्य सरकार भी ''सबके के लिए आवास'' के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कारण इस नाम से एक नया विभाग वर्ष 2020–21 में बनाया गया था यह विभाग प्रदेश में आवासीय सुविधाओं का तेजी से विस्तार कर रहा है, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर पक्कें मकान मिल सकें।

(i) डबल इंजन के लाभ को ऐसे समझा जा सकता है कि हरियाणा में मुख्यमन्त्री शहरी आवास योजना और मुख्यमन्त्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 को क्रमशः प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी और प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे लाभार्थियों को महाग्रामों में 50 वर्ग गज और दूसरे गांवों में 100 वर्ग गज के प्लॉट हरियाणा सरकार द्वारा और इन पर निर्माण लागत की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2025–26 में हाउसिंग बोर्ड का विलय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में किया जाएगा।

(iii) राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के माध्यम से शहरी प्रवासियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को स्वच्छ और किफायती किराये के आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह पहल उन लोगों के लिए अल्पकालिक किराये के आवास का विकल्प देगी, जो अपना घर खरीदना नहीं चाहते। इसके तहत, सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1,600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर पारदर्शी प्रणाली के

माध्यम से किराये पर देने के लिए एक पायलट परियोजना लागू की जाएगी।

90. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 605.30 करोड़ रुपये को 303.8% से बढाकर वर्ष 2025–26 में 2444.27 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

अवसंरचना

91. हरियाणा, विशेष कर प्रदेश का एनसीआर क्षेत्र, देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है, जहां विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और भी अधिक है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सड़कें, परिवहन, औद्योगिक गलियारे और ऊर्जा सुविधाएं विकसित करना समय की माँग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, "अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल विकास का आधार नहीं, बल्कि हर नागरिक की प्रगति और आत्मनिर्भरता की गारंटी है।" हरियाणा का बजट राज्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। जब बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, तभी हरियाणा अंतरराष्ट्रीय निवेश और औद्योगिक क्रांति का केंद्र बनेगा।

92. आज हरियाणा को केंद्र सरकार की ओर से ऐतिहासिक स्तर पर सहयोग मिल रहा है, जिससे सड़कों, रेल, सिंचाई और लॉजिस्टिक्स में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं। 2025–26 के केंद्रीय बजट में हरियाणा के रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 3,416 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है, जो 2009–14 के मात्र 315 करोड़ रुपये से 11 गुना अधिक है। यह ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिससे हरियाणा एक सशक्त औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। गुरुग्राम मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के विस्तार को मंजूरी देकर हरियाणा की शहरी गतिशीलता को नई दिशा दी गई है, जिससे लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी और व्यापार–रोजगार के

नए अवसर खुलेंगे। इसके लिए मैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का तहेदिल से धन्यवाद करता हूँ।

93. गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेन्टर से साइबर हब तक 5,500 करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो लाइन का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा, नमो मेट्रो कॉरिडोर के तहत एन.सी.आर.टी.सी. द्वारा सराय काले खां से धारूहेड़ा होते हुए नीमराना तक नमो मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जबकि सराय काले खां से करनाल तक भी नमो मेट्रो लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही, बहादुरगढ़ से असौदा, बल्लभगढ़ से पलवल और गुरुग्राम के वाटिका चौक से पचगांव तक मेट्रो लाइनों के निर्माण पर अध्ययन किया जा रहा है।

गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण

94. ढांचागत परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय गुणवत्ता व कारिगिरी को बनाये रखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यह प्राधिकरण गुणवत्ता की लिखत–पढ़त व मानकों को परिभाषित करने का कार्य कर रहा है।

भारतीय रेल

95. हमारी सरकार हरियाणा में नई रेल परियोजनाओं, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश की गति और प्रगति दोनों तेज़ हों। 1195 किलोमीटर के 15,875 करोड़ रुपये की लागत से 14 नये रेलवे ट्रैक बनाये जा रहे हैं। बाटा चौंक फरीदाबाद से सेक्टर–56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मैट्रो चलाई जाएगी।

पब्लिक हेल्थ

96. किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जन सुविधाओं का उपलब्ध होना अत्याधिक अनिवार्य है, लेकिन जब बात ग्रामीण क्षेत्र की हो तो यह

मूलभूत आवश्यकता बन जाती है। इन जन सुविधाओं का सभी को लाभ पहुँचे, इसके लिए मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

(i) महाग्राम योजना के तहत इस वर्ष 12 गावों में शहरों की तर्ज पर पीने के पानी व सीवर की सुविधा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त, 150 किलोमीटर की सीवर लाईन व्यवस्था भी की जायेगी।

(ii) पावर प्लांट, उद्योग, सिंचाई और नगर पालिकाओं द्वारा अपशिष्ट जल का उपयोग करने की नीति बनाई जा रही है। आज भी पूरे प्रदेश में 281.65 मीलियन लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल का प्रयोग किया जा रहा है और वर्ष 2028 तक प्रदेश में उत्पन्न होने वाले शत–प्रतिशत अपशिष्ट जल का प्रयोग किया जाने लगेगा, इससे प्रदेश में जल संसाधनों पर दबाव कम होगा।

97. अध्यक्ष महोदय जी, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 4874.45 करोड़ रुपये को 1.6% से बढ़ाकर वर्ष 2025–26 में 4950.96 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

ऊर्जा

98. वित्त वर्ष 2025–26 में ऊर्जा विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं:–

(i) पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में उठाए गए कईं क्रांतिकारी कदम के कारण बिजली उपक्रमों का कुल संप्रेषण एवं व्यावसायिक घाटा वर्ष 2014–15 के 30 प्रतिशत से घटकर 10.4 प्रतिशत रह गया है। इन कदमों के कारण बिजली उपक्रमों की कार्यशैली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए है।

(ii) यह सारे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी वर्ष 2023–24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में यूएचबीवीएन ने प्रथम स्थान पाया है।

इतना ही नहीं पूरे देश में दूसरा स्थान डीएचबीवीएन को मिला है। हमारे राज्य के लिए यह एक एतिहासिक उपलब्धि है।

(iii) पूर्व मुख्यमन्त्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में **म्हारा गांव जगमग गांव** योजना के तहत 24 घन्टे बिजली देने का प्रावधान किया था । मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 5877 गांवों में 24 घन्टे बिजली दी जा रही है। बाकि बचे 1376 गांवों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में हम वित्त वर्ष 2025–26 में एक नई स्कीम लाएंगे।

(iv) वर्ष 2014 में प्रदेश में कुल बिजली उपलब्धतता 10,729 मेगावॉट थी जो आज बढ़कर 16,015 मेगावॉट हो गई है। इसे अगले 7 वर्षों में बढ़ाकर लगभग 24,000 मेगावॉट करने का सरकार का लक्ष्य है, जिससे की हर उपभोक्ता को शत–प्रतिशत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(v) यमुनानगर में 1X800 मेगावॉट अल्ट्रासुपर क्रिटीकल थर्मल प्लान्ट की स्थापना का कार्य लगभग 7272 करोड़ रुपये की लागत से भारत सरकार के उपक्रम बीएचईएल की मदद से शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा और मार्च 2029 तक पूरा कर दिया जायेगा।

(vi) राज्य सरकार ने आरजीटीपीपी, हिसार में 1X800 मेगावॉट अल्ट्रासुपर क्रिटीकल विस्तार ईकाई योजना लगाये जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है और पानीपत में 2X800 मेगावॉट अल्ट्रा सुपर क्रिटीकल परियोजना लगाये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(vii) हरियाणा विद्युत खरीद केन्द्र ने 800 मेगावॉट फर्म और डिस्पैचेबल अक्षय ऊर्जा की खरीद के लिए सतलुज जल

विद्युत निगम लिमिटेड के साथ बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए है जिसके मई 2026 से चालू होने की उम्मीद है। इस 800 मेगावॉट फर्म और डिस्पैचेबल अक्षय ऊर्जा क्षमता में 1115 मेगावॉट सौर, 896 मेगॉवाट पवन व 938 मेगावॉट बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली क्षमता शामिल है।

(viii) प्रधानमन्त्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अर्न्तगत अब तक 14250 घरों पर रूफटॉप सोलर लगा दिये गये है तथा 31.03.2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2 किलोवॉट तक के कनैक्शन वाले अन्तोदय परिवारों को अधिकतम 1,10,000 रुपये की सब्सीडी दी जायेगी।

(ix) गांवों की सड़कों पर व अमृत सरोवरों पर सोलर लाईट लगाये जाने के लिए ₹4000/– व ऊँचे खम्बे पर लगे लाईट के लिए ₹20,000/– की सब्सिडी दी जायेगी। वर्ष 2025–26 में ऐसी 20,000 लाईटें लगाई जाएंगी।

99. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025–26 में 6379.63 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूँ ।

क्षेत्रिय परिवहन व यातायात

100. वित्त वर्ष 2025–26 में यातायात को और सुलभ बनाने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैंः–

(i) 500 Non AC standard BS-VI, 150 HVAC, 375 ई–बसों की खरीद की जाएगी।

(ii) PPP-Public Private Partnership के तहत पिपली, करनाल, सेक्टर–36 A/12A गुरुग्राम, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद), सोनीपत के बस अड्डे बनवाये जाएंगे।

(iii) 71 करोड़ रुपये की राशि से ट्रांसपोर्ट भवन बनाया जाएगा।

(iv) सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी।

(v) बसों की रेलवे जैसे GPS के माध्यम से लाइव ट्रैकिंग को आम जनता के लिए मुहैया करवाया जायेगा।

(vi) वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से, सरकार अपने विभागों में विद्युत संचालित गाड़ियां खरीदेगी। हरियाणा रोडवेज भी लंबे रूटों पर विद्युत संचालित बसों की खरीद करेगी। एक डीजल बस को विद्युत संचालित बस में परिवर्तन करने से उसके 10 साल के जीवनकाल के दौरान 1.50 लाख लीटर डीजल की बचत संभव होगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अपने कुल बेड़े में 30% विद्युत संचालित वाहन शामिल करना है।

(vii) परिवहन वाहनों के लिए वार्षिक मोटर वाहन कर के स्थान पर आजीवन कर लगाया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में स्थापित किए जाएंगे।

(viii) हर जिले में बसों की साफ–सफाई के लिए ऑटोमेटिक बस वॉशिंग मशीन व बस अड्डों की सफाई के लिए मशीन की व्यवस्था की जायेगी।

(ix) PPP-Public Private Partnership के तहत मोटर व्हीकल की फिटनेस के लिए ऑटोमैटिक टैस्टिंग स्टेशन लगाये जायेंगें। मोटर व्हीकल टैक्स को वन टाईम टैक्स में परिवर्तित कर टैक्स की व्यवस्था का सरलीकरण किया जायेगा।

101. अध्यक्ष महोदय जी, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 3088.52 करोड़ रुपये को 9.71% से बढ़ाकर वर्ष 2025–26 में 3388.47 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

नागरिक उड्डयन

102. अध्यक्ष महोदय, यह सर्वत्र हर्ष का विषय है कि हमें भारतीय विमानपतन प्राधिकरण से हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस इस 13 मार्च को प्राप्त हो गया है। अब शीघ्र ही हिसार से अयोध्या, जयपुर, चण्डीगढ, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा जल्द ही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए नए प्रस्तावित कदम इस प्रकार है:

(i) Haryana Aerospace and Defence Policy, 2022 के तहत हरियाणा को रक्षा सम्बंधित हथियारों की व अन्य उपकरणों के बनाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और 2988 एकड़ जमीन हिसार में चिन्हित की गई है। यहॉ पर Aerospace, defence, Food processing, Aircargo, Warehouse, Textile जैसी औद्योगिक इकाईयों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ii) गुरुग्राम में 16 एकड़ भूमि पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा ताकि देश के दूसरे कोनों जैसे सालासर, खाटूश्याम जी, पिताम्बरी माता व चण्डीगढ़ को हेलिकॉप्टर के माध्यम से जोड़ा जा सके।

(iii) विद्यार्थी पायलट प्रशिक्षण के लिए 10 सिंगल इंजन और 2 डबल इंजन प्रशिक्षु जहाज खरीद किये जाएंगे ताकि प्रशिक्षु पायलटों के प्रशिक्षण में लगने वाले लगभग 3 से 4 वर्षों के समय को घटाकर एक वर्ष किया जाएगा, इससे हरियाणा के युवाओं को हवाई क्षेत्र में मिलने वाले रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी।

103. अध्यक्ष महोदय जी, मैं वर्ष 2025–26 में 516.26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूँ।

पर्यटन एवं विरासत

104. हरियाणा में पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा निवेश करना समय की जरूरत है। इसलिए हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि हर परियोजना से लोगों को लाभ मिले और विकास निरंतर गति से चलता रहे। हरियाणा को ओर अधिक पर्यटनशील बनाने के उद्देश्य से मैं कुछ पहलों का वर्णन करना चाहता हूँः–

(i) हरियाणा पर्यटन विभाग अपने टुरिस्ट कॉम्पलैक्सों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पीपीपी (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) के तहत वर्ष 2025–26 में कम से कम पांच काम्पलैक्स को लीज पर देना सुनिश्चित करेगा।

(ii) अर्न्तराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में मेले के मूलभूत ढांचे को अपग्रेड कर मेले का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाएगा।

(iii) प्रदेश भर में कई विख्यात मेलें लगते हैं, इनको भी और भव्य तरीके से मनाने के लिए विभाग द्वारा सहयोग किया जायेगा।

(iv) लोहारू फोर्ट, भिवानी को पर्यटन के लिए विकसित किया जायेगा।

(v) राखीगढी को विश्वस्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करेंगें व वार्षिक स्तर पर राखीगढी मेला मनाया जाएगा।

(vi) सभी पर्यटन व पुरातत्व केंद्रों पर टूरिस्ट गाईड की व्यवस्था करवाई जाएगी, जिन्हे आवश्यक कौशल का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।

(vii) सरकार द्वारा ज्योतिसर, कुरूक्षेत्र में महाभारत अनुभव केन्द्र का विकास किया जा रहा है, जिसकी कुल परियोजना लागत

205.58 करोड़ रुपये है । इस पार्क का उद्देश्य महाभारत की महाकाव्य कथा को जीवंत बनाना है, जिसमें 80% कार्य पूरा हो चुका है।

(viii) अग्रोहा में पुरातात्विक स्थल की खुदाई का कार्य जल्द ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सहयोग से प्रारंभ किया जाएगा। साइट पर वनस्पति सफाई का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। अग्रोहा विकास परियोजना के अगले चरण में साइट संग्रहालय और इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना, लाइट एंड साउंड शो का आयोजन और प्लैनेटेरियम (तारा मंडल) का निर्माण शामिल है। इस परियोजना से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फार्म स्टे और होम स्टे परियोजनाओं की संख्या को 100 तक बढाया जाएगा।

(ix) यादवेन्द्र गार्डन, पिंजौर व टिक्कर ताल, मोरनी को भारत सरकार की मदद से पुनः विकसित किया जायेगा।

105. अध्यक्ष महोदय जी, मैं वर्ष 2025–26 में 262.31 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूँ।

लोकनिर्माण व सड़कें

106. वित्त वर्ष 2025–26 में लोक निर्माण विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं:–

(i) 6500 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत आगामी वर्ष में की जाएगी, इसके अतिरिक्त समय आधारित तरीके से सड़कों की मरम्मत किए जाने की योजना बनाई जायेगी ताकि हर सड़क की प्रत्येक पॉच साल में मरम्मत हो जाए।

(ii) गोहाना–सोनीपत, भिवानी–हांसी व गुरूग्राम–पटौदी का चारमार्गीयकरण व रेवाड़ी बॉयपास का कार्य प्रगति पर है। बल्लभगढ से जेवर एयरपोर्ट के लिए राजमार्ग का निमार्ण

किया जा रहा है। दिल्ली–जयपुर राजमार्ग पर बिलासपुर चौंक, पंचगांव, राठीवास, कापडीवास, साल्हावास व बनीपुर चौंक पर फ्लाईओवर का कार्य किया जा रहा है। दिल्ली–रोहतक रोड पर अंडरपास बनाने का कार्य किया जा रहा है। अम्बाला–शामली व अम्बाला–कालाआम्ब राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पंचकूला–यमुनानगर पर सैक्टर–26, 27 के लिए अंडरपास का कार्य किया जा रहा है। जीरकपुर व पंचकूला में यातायात की भीड़ कम करने के लिए, जीरकपुर बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है।

(iii) अम्बाला रिंग रोड की तर्ज पर भिवानी व हिसार रिंग रोड़, पेहवा–कुरूक्षेत्र–यमुनानगर रोड़ का कार्य भी नेशनल हाईवे अर्थोरिटी के द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा।

(iv) मैं जिला कुरूक्षेत्र में एक विश्राम गृह और लाडवा में एक न्यायालय परिसर के निर्माण का प्रस्ताव रखता हूँ।

(v) सड़कों की सुरक्षा में सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग की सभी 3500 किलोमीटर 12 फीट चौड़ी सड़कों को मार्च, 2027 तक 18 फीट चौड़ा किया जाएगा।

107. अध्यक्ष महोदय जी, मैं वर्ष 2025–26 में 4830.73 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूँ।

सिंचाई एवं जल संसाधन

108. वित्त वर्ष 2025–26 में सिंचाई एवं जल संसाधन से सम्बंधित मेरे निम्न प्रस्ताव हैंः–

(i) हमारी सरकार ने नहरों के विस्तार, जल संरक्षण योजनाओं और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने पर विशेष ध्यान दिया है। जल प्रबंधन को और सशक्त बनाने के लिए आगामी वर्ष में बारिश के दिनों में नदियों से आने वाले बाढ के पानी के प्रबंधन के लिए "मुख्यमंत्री जल संचय योजना" के तहत

मनरेगा की सहायता से कार्य करवाते हुए 100 तलाबों का निर्माण किया जाएगा। खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के प्रबंधन के लिए 2200 पानी के टैंकों का निर्माण किया जाएगा और 100 करोड़ रुपये की लागत से लिफ्ट सिंचाई परियोजना मे लगे हुए पुराने पम्पों को बदला जाएगा। सतलुज–यमुना लिंक कैनाल के माध्यम से हरियाणा की जनता को उसके हक का पानी पंजाब से लेकर दिलवाया जायेगा।

(ii) हरियाणा सरकार भूजल दोहन से संबंधित NOC नीति की समीक्षा कर रही है। औद्योगिक/बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अत्यधिक दोहित क्षेत्रों में NOC की अवधि एक से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह तीन वर्ष होगी। खनन परियोजनाओं के लिए भी यह अवधि एक से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी। इस नीति से परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया सुगम और प्रभावी बनेगी। इसके माध्यम से निवेश और सतत विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

109. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 5443.38 करोड़ रुपये को 10.7% से बढाकर वर्ष 2025–26 में 6024.72 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

सैनिक और अर्ध–सैनिक कल्याण

110. सैनिक और अर्ध–सैनिक कल्याण हेतू मेरे निम्न प्रस्ताव है।

(i) भारतीय सेना एवं अर्ध–सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से HKRN में उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा। इससे इच्छुक भूतपूर्वक सैनिकों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में सुरक्षा सेवा कार्यों को प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

(ii) चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए "सशस्त्र बल तैयारी संस्थान" का निर्माण

किया जाएगा। इन संस्थानों के लिए मैंने प्रतिवर्ष 1000 छात्रों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(iii) मैं शहीद सैनिक व अर्ध–सैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृति योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। जिसके अन्तर्गत कक्षा छठी से 12वीं में पढ रहे बच्चों को प्रति वर्ष ₹60,000/–, डिप्लोमा या स्नातक स्तर में प्रति वर्ष ₹72,000/– व स्नातोकत्तर स्तर में प्रति वर्ष ₹96,000/– दिये जाएंगे।

(iv) सैनिक व अर्धसैनिकों के लिए एक समर्पित हैल्प लाईन शुरू करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

(v) एक नई "वीर उड़ान योजना" की शुरूआत की जाती है, जिसके तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाये जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा और सफल प्रशिक्षण कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर 50 हजार रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी।

(vi) रेवाड़ी मे एक सैनिक संग्रहालय बनाने का भी मेरा प्रस्ताव है।

111. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 115.65 करोड़ रुपये को 17.1% से बढाकर वर्ष 2025–26 में 135.41 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

पर्यावरण वन, जीव जन्तु एवं प्राकृतिक संसाधन

112. पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैः–

(i) आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसा तरीका है जिसमें हम चीजों को इस्तेमाल करने के बाद फेंकने के बजाय, उनका दोबारा इस्तेमाल करते है। इसमें कचरा कम करना, चीजों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल

करना, और जो चीजें बच जाती है उन्हे फिर से काम में लेना शामिल हैं।

इस कड़ी में हरियाणा सरकार दारा वाहनों की scrappage नीति बनाई गई है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि ई वेस्ट (e-Waste) प्रबंधन की नई नीति बनायेगें। हरियाणा की उद्यम एंवम रोजगार नीति में शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्रक्रिया को अपनाने वाली तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औघोगिक ईकाइयों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा। हरियाणा सरकार इस दिशा में लोगो को जागरूक करने एंवम इस क्षेत्र में कौशल विकास करने पर विशेष बल देगी। इस अवधारणा को साकार करने में सरकार प्राइवेट कम्पनीयों, राष्ट्रीय एंव अंतराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करेगी तथा दुनिया भर में जो भी अच्छे तरीके (Best practices) इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको अपनाने को प्रयास करेगी।

(ii) गुरूग्राम व नूंह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाने का काम शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वित वर्ष 2025–26 में समुचित राशि का प्रबंध किया जाएगा।

(iii) यमुनानगर में फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट बनाया जाएगा।

(iv) प्राण वायु देवता पेंशन योजना के अन्तर्गत सम्मानित किये जाने वाले योग्य पेड़ो की पहचान करने के लिए नया सर्वेक्षण किया जायेगा।

(v) दुर्लभ व संकटग्रस्त देसी वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए योजना बनाकर इन प्रजातियों के जीन–पूल को सुरक्षित किया जायेगा।

(vi) IMT मानेसर गुरूग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा।

(vii) पूजा–अर्चना के उपरान्त विर्सजन, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रिसाव के चलते नदियों (घग्गर व यमुना) में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक नई व्यवस्था बनायेगा जिसके तहत नदियों के किनारे पर निर्धारित जगह पर विर्सजन की व्यवस्था कर लोगों की आस्था का सम्मान किया जायेगा।

(viii) हरियाणा सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ तकनीकी व वित्तीय सहयोग के लिए अनुबन्ध करेगी जिसके अर्न्तगत वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए आने वाले 6 वर्षो में 3647 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।

113. अध्यक्ष महोदय जी, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 538.54 करोड़ रुपये को 32.7% से बढाकर वर्ष 2025–26 में 714.89 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

सूचना एवं जनसंपर्क

114. अम्बाला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 538 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन "आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक" का कार्य वित्त वर्ष 2025–26 में पूरा करके इसका लोकार्पण किया जायेगा।

115. हमारी लोकप्रिय "मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना" के अन्तर्गत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ के दर्शन और प्रयागराज के महाकुम्भ में संगम स्नान करवाया गया। वित्त वर्ष 2025–26 में माता वैष्णो देवी और शिरडी सांई मन्दिर के लिए यात्राएं शुरू करवाई जाएगी।

116. सरस्वती नदी और राखीगढ़ी सभ्यता हमारी विशाल सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर है। इसको पुर्नजीवित करने के लिए मैं "हरियाणा सप्त सिन्धु सरस्वती साहित्य, कला व संस्कृति" के नाम से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाए जाने और इसके लिए वित्त वर्ष 2025–26 में 25 करोड़ रुपये की राशि देने का प्रस्ताव रखता हूँ।

117. गुरू रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पीपली में एक स्मारक बनाने की घोषणा भी गत वर्ष की गई थी। मैं इस स्मारक की नागरिक सहभागिता बढ़ाने व इसके पर्यवेक्षण व प्रशासन के लिए एक पृथक ट्रस्ट की स्थापना व इसे प्रारम्भिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन का प्रस्ताव भी रखता हूँ।

118. मुगलों के अत्याचर के विरूद्ध आवाज उठाने वाले और खालसा राज के संस्थापक और वीरता की प्रतिमूर्ति बाबा बन्दा सिंह बहादुर के लोहगढ़ ट्रस्ट को स्मारक के निर्माण व प्रशासन के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन का प्रस्ताव भी रखता हूँ।

119. सरकारी कर्मचारियों के लिए 'कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट' सुविधा की तर्ज पर वित्त वर्ष 2025–26 में यह सुविधा मीडियाकर्मियों को भी प्रदान करने का मेरा प्रस्ताव है।

120. हमारे प्रदेश में तीज, त्यौहार, मेले और उत्सव सभी वर्गों में उत्साह एवं हर्षोल्लास की भावना का संचार करते हैं। मैं ऐसे सभी अवसरों पर जनभागीदारी के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

121. सिखों के गौरवशाली इतिहास और देश व मानव मात्र के लिए सिख धर्म के योगदान को नई पीढ़ियों को बताने के लिए भी पिपली में सिख संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई थी। एचएसवीपी द्वारा इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

122. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025–26 में 262.31 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूँ।

महिला एवं बाल विकास

123. सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे हिंसा एवं भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शान से रह सकें तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ एक सुरक्षित वातावरण में विकास की पूर्ण सुविधाओं में पले बढ़ें। विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता नीतियों की पहल और कार्यक्रम, बच्चों के अधिकारों के बारे में जागृति फैलाने, उनकी शिक्षा, पोषाहार और संस्थानात्मक सहायता आदि के माध्यम से बच्चों का विकास, देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करना है।

124. 1 अगस्त, 2022 से विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों को तीन प्रमुख मिशनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन शक्ति तथा मिशन वात्सल्य। वर्ष 2025–26 के लिए विभाग निम्न नए कदम उठाएगाःकुपोषण एक ऐसा चक्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है यदि इसका समय पर निदान न किया जाए तो इससे आने वाली पीढ़ी के शारीरिक व मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं 12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि खर्च करके 80 हजार कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किये जाने का प्रस्ताव रखता हूँः–

(i) भारत सरकार द्वारा नूह जिले में लड़कियों के लिए किशोरी योजना चलाई जा रही है। मैं इस योजना को 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि से सभी 22 जिलों में लागू किये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(ii) महिलाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आज बड़ा योगदान दे रही है। कामकाजी महिलाओं के लिए मैं पंचकूला, पानीपत,

सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरूग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(iii) व्यापार में महिलाओं को मौका दिये जाने के लिए सरकारी संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकाय, शैक्षिणिक संस्थानों व अन्य किसी भी सरकारी भवन में चल रही कैंटिनों के एक तिहाई टेंडर महिला स्वंय सहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर अलॉट किये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(iv) 2000 आंगनवाडी केंद्रों को 81.63 करोड़ रुपये की धनराशि से चरणबद्ध तरीके से प्ले स्कूल में परिवर्तित करने का भी मैं प्रस्ताव रखता हूँ।

(v) 2000 आंगनवाडी केंद्रों को सक्षम आगंनवाडी केंद्रों में परिवर्तित करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

125. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 1008.44 करोड़ रुपये को 36.1% से बढाकर वर्ष 2025–26 में 1372.10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

समाज कल्याण

126. यह बजट समाज के सबसे वंचित वर्गो को सशक्त बनाने, समुदायों के उत्थान और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। मैं समाज कल्याण के लिए निम्न प्रस्ताव रखता हूँः–

(i) हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता देने के लिए प्रो–एक्टिव पेंशन मोड अपनाया है। इस के तहत वृद्धों, दिव्यांगों, विधवाओं, निराश्रित बच्चों, विद्युरों और अविवाहित पुरुषों के लिए पेंशन योजनाओं का लाभ घर बैठे बिना आवेदन के मिल जाता है। वर्ष 2022 से अब तक कुल 5,43,663 लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रो–एक्टिव पेंशन मोड के माध्यम से 1093.40 करोड़ रुपये की राशि सीधे

ट्रांसफर की गई है। यह संतोष की बात है कि आज विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल 34,55,968 लाभार्थियों के खातों में प्रतिमाह लगभग 1041.83 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की जा रही है।

(ii) वित्त वर्ष 2025–26 में हरियाणा सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। अब 1 अप्रैल से 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वितीय सहायता प्रदान की जाएगी। हीमोफिलिया थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। इन तीन बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों को मौजूदा किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत यह लाभ दिया जाएगा।

(iii) प्रदेश में **"दिव्यांगजन कोष"** की स्थापना भी की जायेगी जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान का मेरा प्रस्ताव है।

(iv) प्रधानमन्त्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को बैंक टाईअप योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले सब्सिडी के लाभ को 10% से बढाकर 50% किया जाता है।

(v) पिछडे वर्ग के उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपये का ऋण हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसके लिए निगम को 50 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।

(vi) हमने महिलाओं को प्रति माह ₹2100/–की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए **''लाडो लक्ष्मी योजना''** को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 में इसके लिए मैंने 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

127. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 12975.81 करोड़ रुपये को 28.3% से बढाकर वर्ष 2025–26 में 16650.78 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

राजस्व विभाग

128. सर्वप्रथम, मैं प्रदेश के सभी ग्रामीणों की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही लाल डोरा व्यवस्था से प्रदेश को मुक्ति दिलवाई।

129. उन द्वारा प्रदेश के समूचे क्षेत्रफल का ड्रोन से सर्वेक्षण भी शुरू करवाया गया था। यह हर्ष की बात है कि यह कार्य सफलता से सम्पन्न हो गया है। प्रदेश के सभी गांवों में राजस्व रिकॉर्ड को पूर्णत कंप्यूटरीकृत कर दिया है। ततीमा काटकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजस्व रिकार्ड और सजरे को अपडेट करने के लिए 22 जिलों के 10–10 गांवों में पायलट के तौर पर पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रदेश के शेष सभी गांवों में यह कार्य वित्त वर्ष 2025–26 में पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड अद्यतन का कार्य पूरे प्रदेश में स्वतः होता रहेगा।

130. इस सर्वेक्षण की सफलता से अब वित्त वर्ष 2025–26 में राजस्व विभाग निशानदेही का काम राजा टोडरमल के जमाने से चल रही जरीब से करने की विधि की बजाय, रोवर के माध्यम से करने की शुरूआत कर देगा। इससे कम समय में और कम कीमत पर प्रामाणिक निशानदेही हरियाणावासियों को मिलने लगेगी।

131. वित्त वर्ष 2025–26 में, मैंने 250 विभिन्न प्रकार के अग्निशमन वाहन खरीदने के लिए तथा 13 हाईड्रोलिक प्लेटफार्म बहुमंजिला ईमारतों के अग्निशमन हेतु 250 करोड़ रुपये के प्रस्ताव रखें हैं।

132. गांव खेडी मसानिया जिला जींद में अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 29 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान मैंने किया है।

133. कई बार डेवलैर्प्स, बिल्डर्स, सोसायटियॉ एवं प्राधिकरण आदि अलॉटी को अपनी पुस्तकों में अचल संपत्ति का हस्तांतरण तो कर देते है और कब्जा भी दे देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नही करवाते। यह कानून गलत है और इससे सरकार को स्टाम्प डयूटी का नुकसान होता है। अगले वित्तीय वर्ष में इस तरह की सभी सम्पत्तियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अलाटीस अगर एक निश्चित अवधि में ऐसा नही करवाते तो उन्हें मौजूदा कलैक्टर रेट पर स्टॉम्प शुल्क देना होगा।

134. सभी तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री करवाये जाने का कार्य आरम्भ किया जाएगा जिस द्वारा व्यक्ति घर बैठे आवेदन कर सकते है, जिससे यह कार्य अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी हो जाएगा।

135. हरियाणा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (HARSAC) राज्य में भू–स्थानिक अनुसंधान, रिमोट सेंसिंग और GIS अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भूमि उपयोग, फसल निगरानी, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास को सशक्त बनाने में मदद करता है। वित्त वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान की तुलना में हरियाणा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (HARSAC) की आवंटित राशि 23.25 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूं। अतः इस विभाग के बजट में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे उपग्रह डेटा विश्लेषण, AI एकीकरण और क्षमता निर्माण को और बढ़ावा

मिलेगा। इससे हरियाणा की नीतिगत निर्णय प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी होंगी और राज्य में नवाचार व आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

136. मेरा मानना है कि उपरोक्त नई व्यवस्थाओं के लागू होने से राज्य मे स्टाम्प डयूटी की आय में बढ़ौतरी होगी। इसलिए मैं वर्ष 2025–26 में विभाग के लिए 16555 करोड रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

137. अध्यक्ष महोदय जी, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 1808 करोड़ रुपये को 58.48% से बढाकर वर्ष 2025–26 में 2866.58 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

गृह विभाग

138. प्रदेश में वर्ष 2014 में 270 पुलिस थानें थे, आज यह संख्या 429 है। महिला थानों की संख्या जहां 2014 तक 02 थी आज 33 है। महिला पुलिसकर्मी की संख्या 2014 में 6 प्रतिशत थी जो आज बढकर 12 प्रतिशत हो गई है। पिछले 10 वर्षो में 29 साईबर थाने खोले गये है।

139. हरियाणा राज्य को माननीय गृहमन्त्री, भारत सरकार के द्वारा 10 सितम्बर 2024 को साईबर क्राईम हैल्पलाईन नंबर 1930 की बेहतर कार्यप्रणाली/ट्रैकिंग हेतू प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

140. हरियाणा में तीन नये आपराधिक कानूनों; नामतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय न्याय संहिता, 2023; व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; को लागू करने हेतू 31.03.2025 की समय सीमा निर्धारित की है। इन नये आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य होगा। इन कानूनों के क्रियान्वयन से आम नागरिक को समयबद्ध एवं त्वरित न्याय मिलेगा।

141. मादक पदार्थो से सम्बन्धित मामलों की जल्दी सुनवाई तथा सजा सुनिश्चित करने हेतू राज्य के हर जिले में फास्टट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जायेगी। **राज्य स्तर पर एक केन्द्रीकृत NDPS मोनिटरिंग सैल बनाई जायेगी।**

142. हरियाणा पुलिस के आधुनिकरण तथा पुलिस कर्मचारियों को नवीनतम एवं उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने एवं उनकी क्षमता निर्माण हेतू 300 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन का मैं प्रस्ताव करता हूँ।

143. कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेट के लिए 10 करोड़ रुपये का मेरा प्रस्ताव है।

144. जिन जिलों मे साईबर अपराध की संख्या अधिक है उन जिलों में उपमंडल स्तर पर साईबर पुलिस सैल की स्थापना करने का मैं प्रस्ताव करता हूँ।

145. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 7383.28 करोड़ रुपये को 12.6% से बढाकर वर्ष 2025–26 में 8315.30 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

आबकारी एवं कराधान विभाग

146. अध्यक्ष महोदय, यह गर्व की बात है कि हमारा प्रदेश जीएसटी कर संग्रह में भारतवर्ष के बडे राज्यों में द्वितीय उच्चतम विकास दर वाला प्रदेश है। साथ ही, हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी कर संग्रह में ऐसे राज्यो में प्रथम स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राजस्व लक्ष्य 63,348 करोड़ रुपये के मुकाबले 12 मार्च, 2025 तक 58,693 करोड़ रुपये नेट राजस्व आमदनी के तौर पर खजाने में जमा हो चुके हैं।

147. करदाताओं की सहूलियत के लिए सरकार ने वन टाईम सेटेलमेंट योजना (OTS) को स्वीकृती दे दी है जो अगले सप्ताह से लागू हो जायेगी। इसके अन्तर्गत छोटे करदाता जिनकी बकाया

राशि 1 लाख रुपये से कम है, उनके कर, ब्याज और जुर्माने को पूर्णतः माफ कर दिया जायेगा। जिन करदाताओं की बकाया राशि 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की है, उनके ब्याज, जुर्माना और कर की राशि पर 60% माफी दी जाएगी। इस योजना से 1.50 लाख छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। जिनकी बकाया राशि 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच में है, उनकों ब्याज, जुर्माना और कर में 50% की माफी दी जाएगी। कुल मिलाकर लगभग 2 लाख छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा।

148. 2 जनवरी, 2025 को गुरूग्राम में मैंने सीए एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बजट पूर्व बैठक की थी। उनके सुझावों पर विचार–विर्मश करके मैं कुछ नई पहलों और प्रस्तावों का संक्षिप्त वर्णन करना चाहूँगाः–

(i) अभी आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ETO) को कर मामलों में मांग देने के लिए कोई सीमा नहीं है। 1 अप्रैल, 2025 से 2 करोड़ रुपये से अधिक कर की मांग वाले मामलों में अब ईटीओ के बजाय उप–आबकारी एवं कराधान अधिकारी (DETC) को नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया जायेगा।

(ii) हरियाणा जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा–61 के तहत Suomoto जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी अभी आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ETO) है। करदाताओं की परेशानियों को कम करने के लिए हमने निर्णय लिया है कि इस धारा के अंतर्गत Suomoto जांच अब सयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (JETC) के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त ही शुरू की जा सकेगी।

(iii) करदाताओं की सहूलियत के लिए हरियाणा जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा–65 के अंतर्गत किये जाने वाले अब

पिछले तीन से चार वर्षों के ऑडिट एक ही बार में किया जाएगा, ताकि व्यापारियों को विभाग में बार–बार चक्कर न लगाने पड़े।

(iv) एक नई प्रथा शुरू करते हुए हरियाणा जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा–66 में विशेष लेखा–परीक्षण (Special Audit) चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट का पैनल बनाया जाएगा।

(v) पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मैं विभाग के हर ईटीओ तथा डीईटीसी के कार्यालय कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

(vi) कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट, जीएसटी का स्वचालन रिफंड, मासिक की बजाए सलाना आत्म मूल्यांकन, इनवायस की सीमा का 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये करना, अन्य सुझाव मुझे दिए गए। इन सुझावों की जीएसटी कॉउसिल में हरियाणा सरकार की और से पैरवी की जाएगी।

(vii) मैं अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक नया प्रशिक्षण संस्थान बनाये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

149. मेरा मानना है कि उपरोक्त नई व्यवस्थाओं के लागू होने से राज्य के कर संग्रह में बढ़ौतरी होगी। इसलिए मैं वर्ष 2025–26 में विभाग के लिए 68834.91 करोड रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

खनन एंव भूविज्ञान

150. हरियाणा राज्य के 8 जिलों में 42 खदानों में खन्न का कार्य किया जा रहा है, जिससे वर्ष 2024–25 में अब तक 670.23 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई है । वर्ष 2025–26 में अम्बाला व फरीदाबाद जिले में नई खदानें शुरू कर अतिरिक्त 645 करोड़ रुपये की राशि

राजस्व खाते में जमा करवाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

151. अध्यक्ष महोदय जी, मैं वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान 97.22 करोड़ रुपये को 25% से बढाकर वर्ष 2025–26 में 121.52 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय,

152. विभिन्न विभागों के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों तथा सभी विभागों के लिए किए गये कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपये के आवंटन हेतु मैने यह बजट प्रस्तुत किया है। अपनी वाणी को विराम देने से पहले, मैं सिर्फ छह छोटे–छोटे परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बिन्दु इस महान सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। इनमें से पहले तीन बिंदु इस बजट के पारित होने के उपरान्त इसमें शामिल सभी प्रस्तावों के प्रभावी एवं कुशल क्रियान्वन के लिए अति आवश्यक हैं।

153. प्रथम बिन्दु सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। उनके कल्याण हेतू लिए गए संकल्प को पूरा करते हुए, मैंने भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी इस यूपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेआउट तथा 30 प्रतिशत फैमिली पेआउट के रूप में दिया जायेगा। ये दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरान्त दिये जायेगें। सेवानिवृत कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरान्त मिलेगा। इस स्कीम का लाभ आज हरियाणा सरकार में सेवारत लगभग 2 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध होगा।

154. दूसरा बिन्दु कुछ शहरों मे सरकारी आवास की कमी का है। आने वाले वर्षो में हम हर शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्व है।

155. तीसरा बिन्दु, गत 3 और 4 मार्च को सभी विधायकों और सांसदों के साथ रेड बिशप पंचकूला में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में अनेक बार उठाए गये एक विषय से जुड़ा है। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि वर्ष 2020 और 2021 में कोविड महामारी के कारण उनके क्षेत्रों में कई सरकारी परियोजनाएं प्रभावित हुईं। कुछ काम रूक गए, कईयों में विवाद हो गए और कुछ तो अदालतों में पहुंच गए। वर्ष 2024 में पहले लोक सभा और फिर विधानसभा के आम चुनावों में लगी चुनाव आचार संहिताओं के कारण भी कई निर्माण कार्य लम्बित रह गए।

156. मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि वित्त वर्ष 2025–26 में सभी विभागों के रूके हुए और अधूरे कामों को युद्व स्तर पर शुरू करके पूरा करवाया जाना सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए **पीएम गतिशक्ति** की तर्ज पर शीघ्र ही एक नया पोर्टल बनाया जायेगा। इसके माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा सुनिश्चित होगी।

157. अध्यक्ष महोदय, मेरे बाकी तीन बिंदु सभी माननीय सदस्यों से संबंध रखते हैंः–

(i) सर्वप्रथम, कई विधायकों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों बारे व्यक्त की गई मांगो को व्यापक स्तर पर मानते हुए, मैं घोषणा करता हूँ कि वित्त वर्ष 2025–26 में हर शहर में एक 4–5 किलोमीटर लम्बी सड़क को तथा हर जिले में एक 10–15 किलोमीटर लम्बी सड़क को **स्मार्ट मार्ग** बनाया जाएगा। इसी तरह हर शहर में एक पुराने बाज़ार का **स्मार्ट बाज़ार** के रूप में और हर गांव में एक गली का **स्मार्ट गली** के रूप में कार्याकल्प किया जायेगा। इसके लिए आवश्यकता अनुसार सम्बंधित स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा प्राधिकरणों को धन राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ii) दूसरे, मैं इस विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हर माननीय विधायक को अपने–अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि का विशेष प्रावधान करता हूँ। यह राशि तीन किश्तों में दी जायेगी। इसके लिए हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की एकमुश्त सूची अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर देनी होगी। इस सूची में से पहली किश्त में 1.5 करोड़ रुपये की राशि माननीय विधायक द्वारा दी गई वरीयता अनुसार तुरंत जारी की जायेगी। इसी प्रकार, दूसरी किश्त 1.5 करोड़ रुपये की तथा अन्तिम किश्त 2 करोड़ रुपये की होगी। अगली किश्त की राशि पिछली दी गई राशि के 70 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त जारी की जायेगी। मेरा मानना है कि इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि विकास कार्यो के क्रियान्वयन में विधायकों की व्यक्तिगत रूचि बनी रहें। ऐसा होने से विकास कार्यों की प्रगति भी तीव्र होगी।

(iii) तीसरे, यह हर्ष और गर्व का विषय है कि परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ''एक राष्ट्र–एक विधान मंडल'' की सोच को साकार करने के लिए, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के जनवरी, 2025 में हुए पटना सम्मेलन में पारित संकल्पों को जन–जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसके अंतर्गत भारत के संविधान के मूल्यों एवं विशेषताओं को जनता तक यूथ पार्लियामेंट, महिला सम्मेलनों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के जन–जन तक पहुंचाया जाएगा। मैं आपको हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा विधानसभा की इस विशिष्ट पहल में हर संभव प्रशासनिक तथा वित्तीय सहयोग का आश्वासन देता हूँ।

158. अध्यक्ष महोदय, यह बजट हरियाणा के हर वर्ग के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मैं इस महान सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूँ कि हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में मेरा पहला बजट भाषण आपने पूरे धैर्य से सुना।

159. मेरे सारे बजट प्रस्तावों के पीछे जो मेरी सोच रही वह गुरु रविदास जी के इन शब्दों से प्रकाशित थी :–

ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न।

छोट–बड़ो सभ सम बसै, रैदास रहे प्रसन्न।।

160. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक छोटे–बड़े को एक दृष्टि से देखते हुए प्रत्येक हरियाणवी परिवार को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

161. इन शब्दों के साथ, मैं वित्त वर्ष 2025–26 के बजट प्रस्तावों को इस गरिमामयी सदन के विचार मंथन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

वंदे मातरम!

जय हिंद!

11694—F.D.—H.G.P.,Pkl.